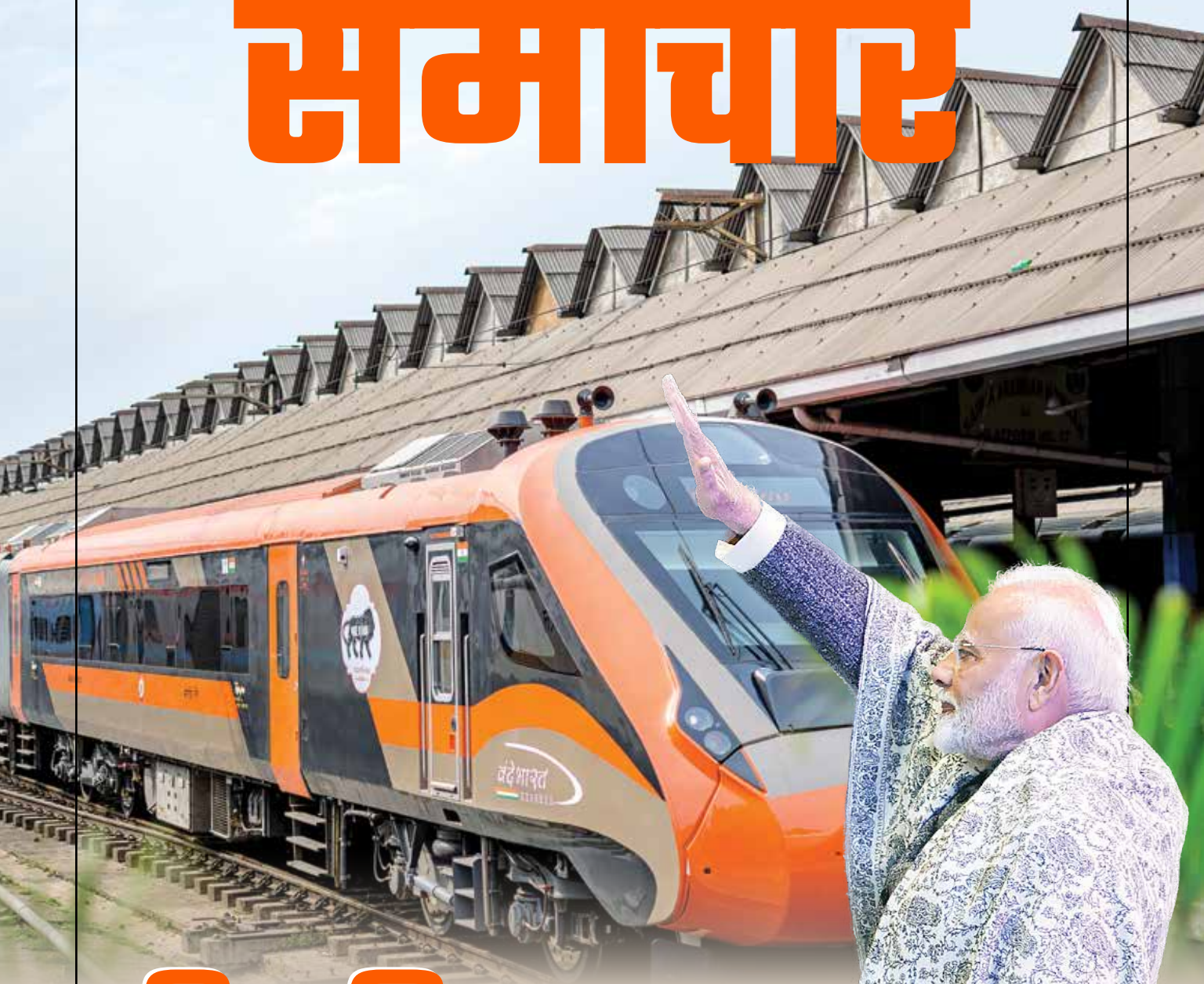
वर्ष: 5 अंक: 15

1-15 फरवरी, 2025 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

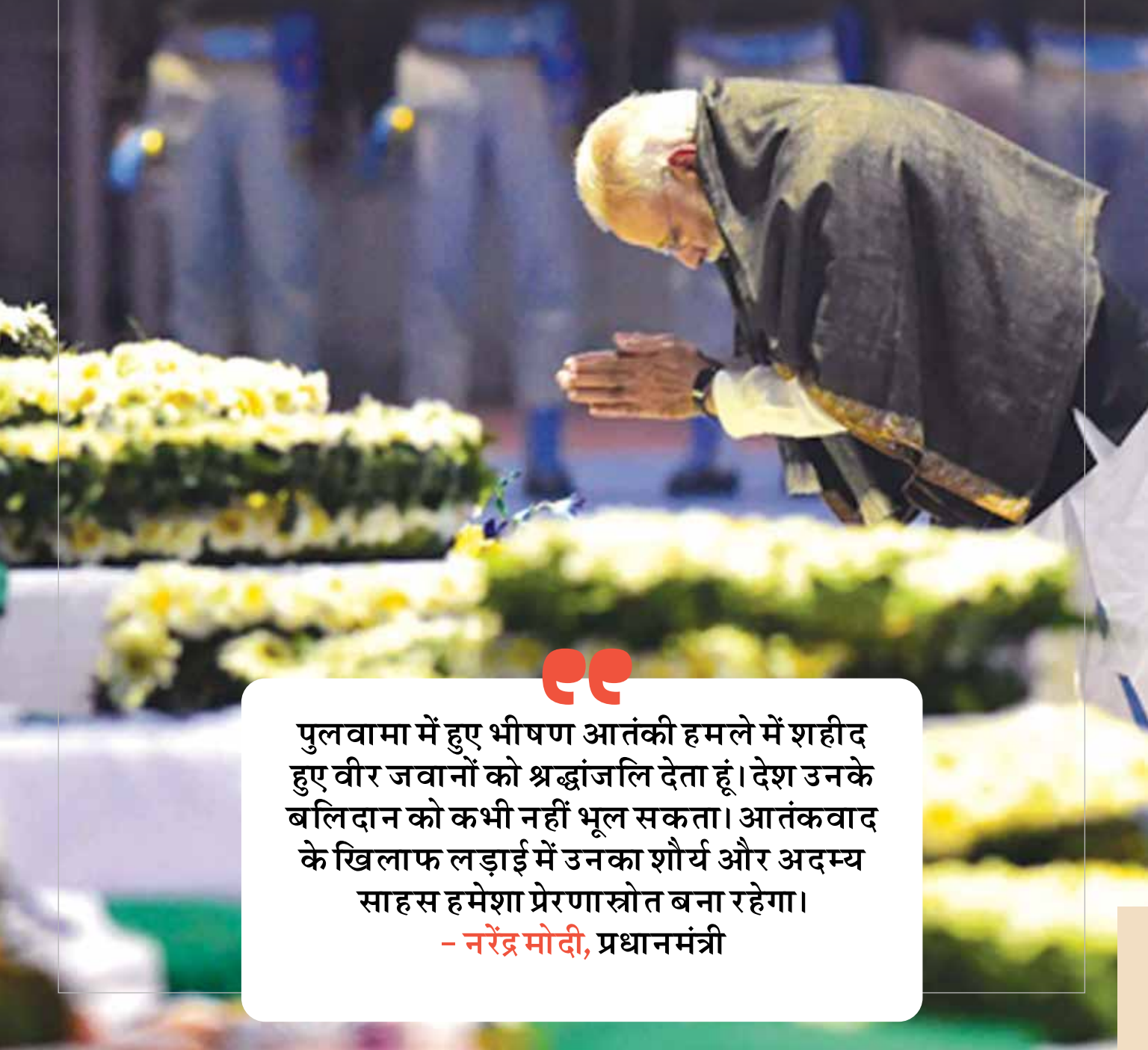


विकसित भारत विकसित रेलवे

राष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल बीते एक दशक में परिवर्तन की साक्षी बनी है तो भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ आधुनिक और स्वदेशी वंदे भारत जैसी ट्रेन दे रही है विकास को नई गति...

नमन

साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया। देश के 40 बहादुर बेटों को वीरगति मिली। इस दिन हर भारतवासी की आंखें नम थीं तो साथ ही उद्घोष भी था, आतंक के विरुद्ध युद्ध का। ठीक 11 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर नए भारत ने अपने मजबूत इरादों की झलक भी दिखा दी। पुलवामा के कायराना आतंकी हमले की छठवीं बरसी पर देश कर रहा है अपने वीर जवानों को नमन...



पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका शौर्य और अदम्य साहस हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 5, अंकः 15 । 1-15 फरवरी, 2025

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर
श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह



13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

भारतीय रेल आधुनिकता के रंग में सुगम यात्रा की प्रतीक



भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है ऐसे में गति के साथ-साथ भारतीय रेल आज दिल, समाज और लोगों को अवसर से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। वंदे भारत, नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, सुरक्षित पटरी, सुविधायुक्त स्टेशन को तकनीक से जोड़कर रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है। 2025 की शुरुआत से ही भारत ने रेल परियोजनाओं की ताबड़तोड़ शुरुआत की है। इस शताब्दी के तीसरे दशक में रेलवे का कायाकल्प बन चुका है राष्ट्र का मिशन... | 12-31

पॉडकास्ट

मेरे हर कार्य का मानदंड "नेशन फर्स्ट"



बचपन में सामान्य विद्यार्थी से राजनेता और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद की यात्रा में आए अहम पड़ावों के बीच असफलता से सीख लेकर सफलता का सफर | 7-11

76वां गणतंत्र दिवस

कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति, अनूठी सांस्कृतिक विविधता



इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रहे मुख्य अतिथि | 56-59

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व - सुषमा स्वराज
भारत, भारतीय, भारतीयता और सुषमा स्वराज... | 6

मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल शहरी जीवन का नया आधार
भारत में जल्द होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क | 32-34

21वीं सदी का जम्मू-कश्मीर लिख रहा विकास का नया अध्याय
12 किमी लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन | 35-37

भगोड़े अपराधियों पर अब भारतपोल से लगेगी लगाम
पुलिस भी सीधे इंटरपोल की ले सकेगी मदद | 38-39

ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 : गांव के विकास से राष्ट्र का विकास
पीएम मोदी का ध्येय विकसित भारत-2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत | 40-41

भविष्य की प्रौद्योगिकी का केंद्र बनेगा आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश को पीएम मोदी ने दी दो लाख करोड़ रुपये की सौगात | 42-43

वैश्विक विकास में प्रवासी भारतीय सबसे आगे
पीएम मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का किया उद्घाटन | 44-45

जनभागीदारी से जनकल्याण
भारत सरकार के वर्ष 2025 के कैलेंडर का अनावरण | 46-47

राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम ने युवाओं से किया संवाद
नई ऊंचाई पर ले जाएगा कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाने का मंत्र | 48-49

भारत की वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक भारतीय मौसम विभाग
आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन | 50-51

दुनिया की मजबूत समुद्री शक्ति बनता भारत
तीन अग्रणी युद्धपोत पीएम मोदी ने किया राष्ट्र को समर्पित | 52-54

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय : 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को भी मंजूरी | 55

मन की बात : 118वीं कड़ी (19 जनवरी 2025)
"कुंभ, पुष्करम, गंगा सागर मेला सद्भाव और एकता को बढ़ावा देते हैं" | 60

प्रकाशक और मुद्रकः योगेश कुमार बवेजा, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रणः** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-316, नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

'ईज ऑफ ट्रैवल'
का मुख्य आधार बन रही भारतीय रेल

सादर नमस्कार।

आज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, देश की विकास यात्रा में नया अध्याय जुड़ रहा है। बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है। बीते 10 वर्षों में सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे का कायाकल्प साक्षात लोगों की आंखों के सामने है। एक दशक पहले तक, वंदे भारत जैसी आधुनिक, सेमी-हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कोई सोच भी नहीं थी। आज वंदे भारत जैसी ट्रेनों का जाल, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, नमो भारत जैसी रेल सेवा साकार होती दिख रही है।

रेलवे की नई पटरियों को बिछाना, विद्युतीकरण के सौ प्रतिशत के करीब पहुंचना, ट्रेन में स्वच्छता जैसी पहल नई क्रांति लेकर आई है। मानव रहित क्रासिंग अब पुराने दिनों की बात हो गई है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हवाई अड्डों जैसी सुविधा लेकर आया है। आज गरीब और मध्यम वर्ग सुगम-सुरक्षित यात्रा यानी 'ईज ऑफ ट्रैवल' का लाभ उठा रहा है। इस 15 फरवरी को स्वदेशी वंदे भारत की शुरुआत के छह वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर भारतीय रेलवे का कायाकल्प हमारी आवरण कथा बनी है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले पॉडकास्ट के संपादित अंश शामिल है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि, प्रवासी भारतीय दिवस, सीबीआई द्वारा विकसित भारतपोल पोर्टल का शुभारंभ, वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, कनेक्टिविटी का पर्याय बनती भारतीय मेट्रो पर विशेष सामग्री, रेडियो पर प्रसारित होने वाले वर्ष 2025 के पहले 'मन की बात' के साथ ही, पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है।

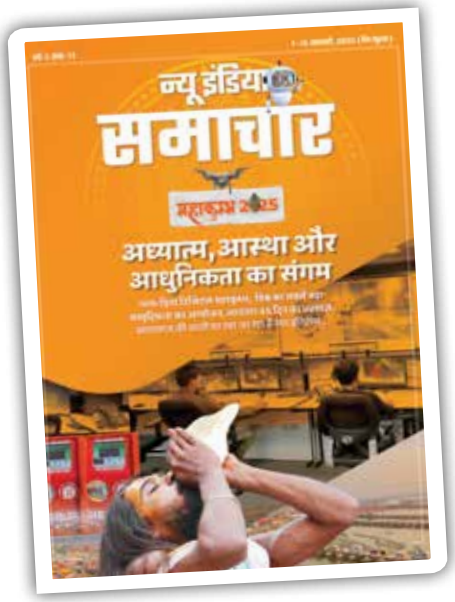
इसके अलावा, इनसाइड कवर में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में कर्त्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन और बैक कवर पर 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस इस अंक की विशेषता है।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...



सरल भाषा में मिलती है जानकारी

आज भारत अपनी विरासत के माध्यम से विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है। दुनिया भारत को उसकी उपलब्धियों के माध्यम से पहचान रही है। ऐसी अंतरराष्ट्रीय जानकारी केवल न्यू इंडिया समाचार पत्रिका से मिलती है। देश की विभिन्न योजना और विकास कार्यों के बारे में सरल भाषा में जानकारी देने के लिए हम आपके आभारी हैं।

tejasprajapati1005@gmail.com

सरकार की योजना और नीतियों के बारे में मिलती है जानकारी

हाल ही में मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के बारे में पता चला और इसके महत्व के बारे में समझ सका। पत्रिका में सरकार की योजनाओं और नीतियों को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। प्रमुख समाचार पत्रों की तुलना में न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में अपने पाठकों के लिए परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, असंगठित क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है।

buchchu1zha@gmail.com

पुस्तकालय के लिए काफी उपयोगी न्यू इंडिया समाचार

मैं एक शैक्षणिक संस्थान में लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत हूं। मैंने न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ी है। ऐसे में मुझे अपने पुस्तकालय के लिए यह पत्रिका काफी उपयोगी लगती है।

राकेश एल. मकवाना

rakeshmakwana.spcc@spec.edu.in

काफी अच्छी लगी न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने को मिली। यह पत्रिका मुझे काफी अच्छी लगी। मुझे न्यू इंडिया समाचार की नियमित प्रति भेजने के लिए धन्यवाद।

डॉ. धरिंदर तायल

tayal1@yahoo.com

ज्ञानवर्द्धक है न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक पत्रिका का हिंदी संस्करण पढ़ने को मिल रहा है। यह एक ज्ञानवर्द्धक पत्रिका है। इसमें सरकार से लेकर देश में होने वाले विकास से संबंधित जानकारी पढ़ने को मिलती है।

manishkhandelwal002@gmail.com

प्रमुख योजना के बारे में मिलती है जानकारी

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका एक अद्भुत माध्यम है जिसके जरिए भारत सरकार की प्रमुख योजना, कार्यक्रम, मंत्रिमंडल के निर्णय, मन की बात का प्रसारण और सम-सामयिक मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। पत्रिका विभिन्न मौजूदा मुद्दों की जानकारी भी देती है।

tejprakashyadav@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-316,
नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

आकाशवाणी समाचार
Akashvani

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी पर सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समाचार सार

भारत में माइक्रोसॉफ्ट का विस्तार



माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई जिसमें भारत में माइक्रोसॉफ्ट के विस्तार से संबंधित चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के महत्वाकांक्षी विस्तार और निवेश योजनाओं के बारे में जानकर प्रसन्नता व्यक्त की। दोनों ने बैठक में तकनीक, नवाचार और एआई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के बारे में सत्य नडेला के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सत्य नडेला। मुझे भारत में माइक्रोसॉफ्ट के विस्तार और निवेश योजनाओं के बारे में जानकर खुशी हुई।

पैरासिटामोल उत्पादन करने की स्वदेशी तकनीक विकसित

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक एवं बुखार कम करने की दवा पैरासिटामोल का उत्पादन करने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इस नवाचार का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप आयातित सामग्रियों पर निर्भरता को कम करके भारत को पैरासिटामोल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। कर्नाटक स्थित सत्य दीप्था फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इस उपलब्धि का उपयोग घरेलू स्तर पर किफायती पैरासिटामोल उत्पादन करने के लिए करेगी। वर्तमान में, भारत कई देशों से पैरासिटामोल के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात करता है।

पीएम की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई चादर



अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पवित्र चादर चढ़ाई। महान सूफी संत की याद में आयोजित होने वाला यह वार्षिक उर्स सद्भाव, आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने दरगाह आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव और सुविधा को बढ़ाने के लिए कई पहलों का अनावरण किया। पीएम मोदी ने किरेन रिजिजू की एक्स पर पोस्ट की प्रतिक्रिया में लिखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर बधाई। यह अवसर सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए।



निरंजना नदी के कायाकल्प की ओर बढ़ाया कदम

भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों में निरंजना (फल्गु) नदी का अपना विशिष्ट स्थान है। झारखंड के चतरा से निकलकर बिहार के गया से बहने वाली यह नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। समय के साथ, घटते जल प्रवाह, प्रदूषण, गाद जमाव और अतिक्रमण के कारण पवित्र नदी अब पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। ऐसे में निरंजना नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक में निरंजना नदी के कायाकल्प और पुनर्जीवन के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है। यह रणनीति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तत्काल समाधान और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है।

महाकुम्भ 2025

दो साल में उगाए गए लगभग 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल

प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुम्भ 2025 के लिए प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं। इससे शहर में आने वाले लाखों भक्तों को शुद्ध हवा एवं स्वस्थ वातावरण मिल रहा है। प्रयागराज नगर निगम ने पिछले दो वर्षों में अनेक ऑक्सीजन बैंक स्थापित करने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग किया है जो अब हरे-भरे जंगलों में तब्दील हो गए हैं। इन प्रयासों से न केवल हरियाली को बढ़ावा मिला है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। निगम ने पिछले दो वर्षों में 55,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शहर में 10 से ज्यादा स्थानों पर वृक्षारोपण किया है।



संपत्तियों की ई-नीलामी के लिए पुनर्निर्मित 'बैंकनेट' पोर्टल का शुभारंभ



वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव ने पुनर्निर्मित ई-नीलामी पोर्टल 'बैंकनेट' का शुभारंभ किया जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से ई-नीलामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। साथ ही यह खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की खोज करने के लिए एक स्थान पर सुविधा देता है। ई-नीलामी पोर्टल पर सूचीबद्ध आवासीय संपत्तियों जैसे फ्लैट, घर और खुले भूखंडों के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि, भवन, दुकान, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि भी शामिल है। सभी विवरणों को एक स्थान पर एकत्र कर, यह संपत्ति ई-नीलामी खोजने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इससे खरीदार और निवेशक के लिए अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है।

सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में अब भाषिणी-सक्षम ई-श्रम पोर्टल उपलब्ध

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने हाल ही में ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता का शुभारंभ किया। ई-श्रम को 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' बनाने के विजन के अनुरूप, यह पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह कदम देश में असंगठित श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। ई-श्रम पोर्टल को 22 भाषाओं में अपग्रेड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषिणी परियोजना का लाभ उठाया गया है। पिछला वर्जन केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था। ■



संवाद और साहस के साथ समर्पण की सुषमा



हरियाणा सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकप्रिय विदेश मंत्री... इन सारी भूमिकाओं से परे सुषमा स्वराज एक ऐसा नाम है... जो संवाद, साहस और समर्पण का प्रतिबिंब बनीं, जिनके लिए सफलता का मतलब गिरने से बचना नहीं, बल्कि और अधिक ताकत तथा स्पष्टता के साथ उठ खड़ा होना था... जन्मदिन पर देश कर रहा है उन्हें नमन...

14 फरवरी, 1952 - 06 अगस्त, 2019

मंगलवार 6 अगस्त 2019: 'प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी' मृत्यु से कुछ घंटे पहले अनुच्छेद 370 की समाप्ति की घोषणा होने के बाद यह उनका आखिरी सार्वजनिक संवाद था, जो इस बात का परिचायक है कि सुषमा स्वराज के लिए एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सामने पद, परिवार, मान-सम्मान नगण्य थे।

14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मी सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुषमा स्वराज ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में सुषमा ने लगातार तीन वर्षों तक एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार तीन बार सर्वक्षेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने सितंबर 2016 में सयुंक्त राष्ट्र में हिंदी में ही भाषण दिया था। उनके इस भाषण की पूरे देश में चर्चा हुई थी। वे विश्व हिंदी सम्मेलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लेतीं थीं। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भी उन्होने अनेक प्रयत्न किए। वे सात बार सांसद और तीन बार विधायक, दिल्ली की पांचवीं और पहली महिला मुख्यमंत्री, 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और विदेश मंत्री रह चुकी हैं।

जब संसद में कहा था 'हां, हम साम्प्रदायिक हैं..'

विचारधारा को लेकर उनका समर्पण और सुस्पष्टता की झलक लोकसभा में दिए उनके उस भाषण से होती है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'हां, हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदेभारत गाने की वकालत करते हैं। हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि हम राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हां हम साम्प्रदायिक हैं, क्योंकि हम अनुच्छेद 370 समाप्त करने की मांग करते हैं।'

मददगार सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने यमन संकट के दौरान अपनी निगरानी में लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित निकालने के मिशन की अगुआई थी। 'ऑपरेशन राहत' के तहत 4,741 भारतीय नागरिकों और 48 देश के 1,947 लोग को बचाया गया था। यमन संकट के दौरान, सुषमा स्वराज ने एक यमनी महिला सबा शॉवेश के एक ट्वीट का जवाब दिया, जो अपने आठ महीने के भारतीय बच्चे के साथ वहां फंसी हुई थी। सुषमा स्वराज ने उसकी मदद भी सुनिश्चित की। एक दूसरे मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आदमी की बहन को बचाया, जिसे यूएई में एक मानव तस्करी गिरोह ने पकड़ रखा था। बात 5 साल की एक पाकिस्तानी लड़की के लिवर ट्रांसप्लांट की हो या सुनने और बोलने में असमर्थ गीता नाम की एक भारतीय लड़की की, जब भी जरूरत पड़ी, सुषमा स्वराज ने मदद करके मानवता की मिसाल पेश की।

उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, सुषमा जी का भाषण प्रभावी होने के साथ-साथ, प्रेरक भी होता था। सुषमा जी के वक्तव्य में विचारों की गहराई हर कोई अनुभव करता था, तो अनुभव की ऊंचाई भी हर पल नए मानक पार करती थी। ये दोनों होना एक साधना के बाद ही हो सकता है। ■

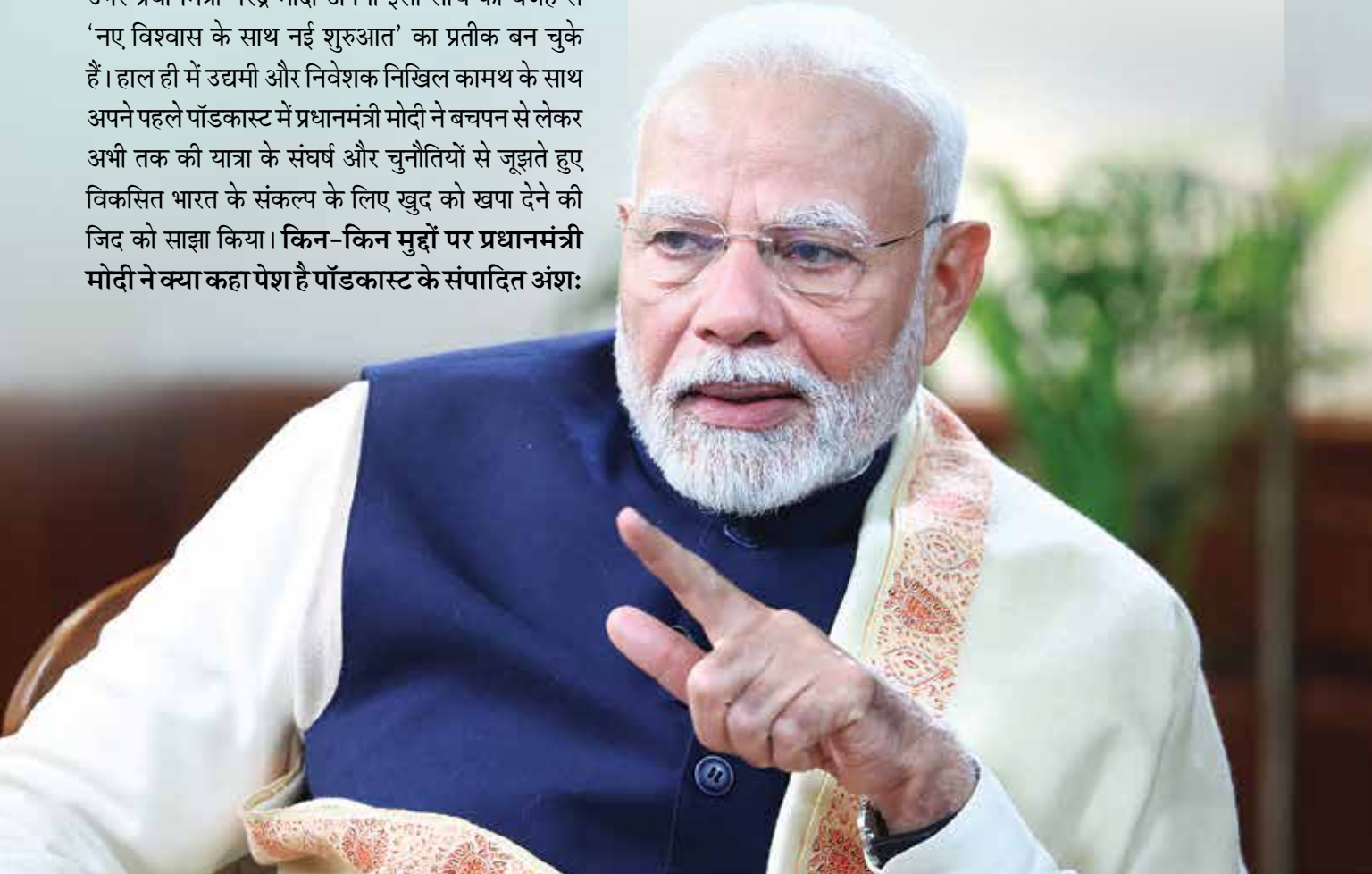
मेरे हर कार्य का मानदंड "नेशन फर्स्ट"

बचपन में सामान्य विद्यार्थी से राजनेता और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद की यात्रा में आए अहम पड़ावों के बीच असफलता से सीख लेकर सफलता का सफर...

थकना, हारना, टूटना-बिखरना जिन्हें मंजूर नहीं। बड़ी से बड़ी चुनौतियों से जूझना, आपदा को भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए अवसर में बदल नया इतिहास रचना। न थकना, न थमना, न रूकना, अथक परिश्रम से केवल आगे बढ़ते जाना और जिनकी हर सोच आधारित है- 'राष्ट्र प्रथम यानी नेशन फर्स्ट' पर। यह नए भारत के मजबूत नेतृत्व की अमिट पहचान बन चुकी है।

युगदृष्टा और साहसिक सुधारवाद के प्रणेता के तौर पर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इसी सोच की वजह से 'नए विश्वास के साथ नई शुरुआत' का प्रतीक बन चुके हैं। हाल ही में उद्यमी और निवेशक निखिल कामथ के साथ अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन से लेकर अभी तक की यात्रा के संघर्ष और चुनौतियों से जूझते हुए विकसित भारत के संकल्प के लिए खुद को खपा देने की जिद को साझा किया। **किन-किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा पेश है पॉडकास्ट के संपादित अंश:**

> **मैं प्रधानमंत्री पद पर अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था। पहले हम यहां थे, अब यहां जाएंगे। अब तीसरे कार्यकाल में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है। मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है। मेरे अरमान बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि मुझे 2047 में विकसित भारत चाहिए।**



अपने बचपन पर

बचपन के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको पता है मेरा जन्म नॉर्थ गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की ही आबादी थी, ऐसा मोटा-मोटा मुझे याद है। मेरा गांव एक प्रकार से गायकवाड स्टेट था। गायकवाड स्टेट की एक विशेषता थी। हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। यहीं के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। यहां के पत्थर-पत्थर में कोई न कोई कहानी है। चीनी विचारक ह्वेन त्सांग ने भी वडनगर में वक्त गुजारा था। पीएम मोदी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझे इसके बारे में बताया। उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा कि पीएम पद संभालने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझे फोन किया और कहा कि हम दोनों के बीच एक बड़ा कनेक्शन है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके गांव वडनगर जाना चाहता हूं। क्योंकि ह्वेन त्सांग वडनगर से जब चीन वापस लौटे तो शी जिनपिंग के गांव में रहे थे।

दोस्त और अपनों के जिक्र पर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया। घर छोड़ा, मतलब सब कुछ छोड़ा। किसी से मेरा संपर्क नहीं था तो बहुत बड़ा गैप हो गया। जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जागीं। एक इच्छा यह जागी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को यह लगे कि अपने आप को बड़ा तीस मार खां बन गया है। क्योंकि, मैं वही हूं, जो सालों पहले गांव छोड़कर गया था। शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम। रात को खाना खाया, गपशप की, बचपन की यादें ताजा कीं। लेकिन मुझे बहुत आनंद नहीं आया और इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, जबकि उनको मुख्यमंत्री नजर आता था। तो वो खाई पटी नहीं और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं। मेरे एक टीचर थे रास बिहारी मनिहार, अभी कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हुआ और वह करीब 93-94 साल के थे।

नेशन फर्स्ट की सोच पर...

प्रधानमंत्री बोले कि मैंने लाल किले से कहा था कि देश को एक लाख ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो राजनीति में आएं और मैं मानता हूं कि लेना, पाना, बनना, यह अगर मकसद है तो उसकी आयु बहुत लंबा नहीं है जी। आंत्रप्रेन्योर के पास जो पहली ट्रेनिंग होती है ग्रो करने की, यहां पहली ट्रेनिंग होती है खुद को खपा देने की, जो है वह भी दे देने की, वहां पर मैं, मेरी कंपनी या मेरा प्रोफेशन नंबर वन कैसे बने, यहां होता है नेशन फर्स्ट, यह बहुत बड़ा फर्क होता है और समाज भी नेशन फर्स्ट की सोच वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है।

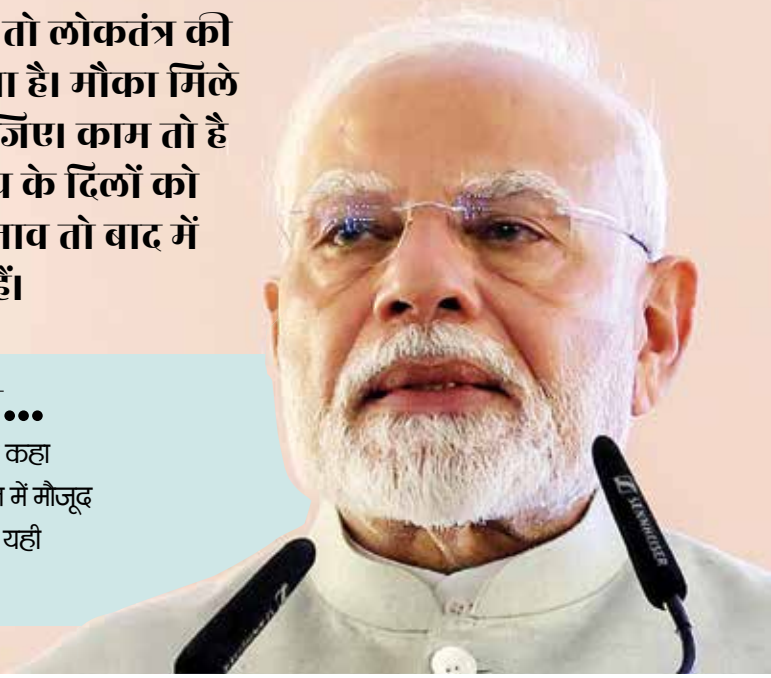




राजनीति में विचारधारा पर

पॉलिटिशियन की आईडियोलॉजी के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीति में आईडियोलॉजी से भी ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। आईडियोलॉजी के बिना राजनीति होगी, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन, आइडियलिज्म आदर्शवाद इसकी बहुत जरूरत होती है। आजादी के लिए गांधीजी का रास्ता अपना था और सावरकर का अलग।

राजनीति में आने का मतलब चुनाव लड़ना ही नहीं होना चाहिए। वो तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। मौका मिले तो लड़ लीजिए। काम तो है जनसामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं।



भारत को विकसित बनाने का वादा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए कुवैत दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि मै वहां एक श्रमिक कॉलोनी में गया। एक श्रमिक ने पूछा कि भारत में मौजूद उसके जिले में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बनेगा? उन्होंने कहा कि यही आकांक्षा है जो 2047 में भारत को विकसित बनाएगी।

वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। मेरे मन में था कि मैं अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूं, क्योंकि मुझे बनाने में उनका बड़ा योगदान है। मैंने कार्यक्रम किया जिसमें करीब 30-32 शिक्षक आए। सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। दो और काम भी मैंने किए। एक तो काफी समय पहले ही घर छोड़ चुका था तो परिवार के कई सदस्य जिनके बच्चे भी हो गए थे। उनको नहीं जानता था। इसलिए सबको बुलाया। उनसे परिचय किया। इसके साथ ही, संघ में काम करने के दौरान कई घरों में जाता था भोजन करने के लिए। उन्हें भी मैंने बुलाया।

राजनीति में युवाओं के आने पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पॉलिटिशियन बनना और पॉलिटिक्स में सफल होना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख-दुख के आप साथी होने चाहिए, आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। आप यह कहो कि मैं तीस मार खां हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए लेकिन वह सफल राजनेता बनेगा यह गारंटी नहीं है। मेरा मत है कि राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए और मिशन लेकर के आएं, एंबीशन लेकर के नहीं।

राजनीति में संवेदनशीलता पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीति में संवेदनशील लोगों की जरूरत है किसी का भला हो तो खुशी हो ऐसे लोगों की जरूरत है। दूसरा विषय है आरोप-प्रत्यारोप तो यह लोकतंत्र में आपको स्वीकार करके चलना चाहिए कि भई आप पर आरोप होंगे, भांति भांति के आरोप होंगे लेकिन आप अगर सही हैं, आपने गलत नहीं किया है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी।

सोशल मीडिया के बदलते दौर और ट्रोलिंग पर

वर्तमान समय में सोशल मीडिया में ट्रोलिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी-कभी लोग मुझे पूछते हैं। खासतौर पर छोटे-छोटे बच्चे पूछते हैं कि आपको दिन-रात इतनी सारी गालियां पड़ती हैं, आपको कैसा लगता है। मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूं। मैं कहता हूं कि मैं अहमदाबादी हूं और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान है कि उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक



असफलताओं से सीखने पर...

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस दिन चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग थी, मुझे कई लोगों ने कहा था कि साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले साहब यह तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल हो जाते हैं, चार-चार छह-छह बार करने के बाद सफलता मिलती है। मैं गया और लास्ट सेकंड में हम बिखर गए। सारे बाहर बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को जितना समझता हूं, लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार एक जो वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे आकर बताया। मैंने कहा चिंता मत कीजिए सभी को मैंने नमस्ते किया। मैं वहां से गेस्ट हाउस गया। लेकिन, सो नहीं पाया। करीब आधे-पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा अगर यह लोग थक न गए हों तो मैं जाने से पहले सुबह 7:00 बजे इनको मिलना चाहता हूं। क्योंकि देश के लिए लॉन्चिंग सफल न हो पाना, बहुत बड़ा झटका था। मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को कहा कि अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेदारी मेरी है, आपने प्रयास किया आप निराश मत होइए। उनका जितना भी आत्मविश्वास था, मैंने जगाया। आप देख सकते हैं, चंद्रयान 3 सफल हुआ।

सबसे बड़े पल का जिक्र...

अपने जीवन में खुशी के सबसे बड़े मौके का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया गोलियां चली, पांच या छह लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा ? श्रीनगर लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगे झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी मां को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी का पल था और दूसरा मन में था कि मां को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहां गया है तो मुझे याद है मैंने पहला फोन मां को किया था। मुझे उस फोन का महात्मय आज समझ आता है। वैसी फीलिंग मुझे और कहीं आई ही नहीं।

अहमदाबादी स्कूटर लेकर जा रहा था और सामने वाले से टक्कर हो गई तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। वह गालियां देने लगा ये जो अहमदाबादी था स्कूटर लेकर ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था, इतने में कोई आया बोला यार भाई तुम कैसे इंसान हो यह गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो। अहमदाबादी बोलता है, दे ही तो रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा। मैंने भी ऐसा ही मन बना लिया है।

भावुकता, मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी पर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे भावुकता से ऊपर रहना होगा। जैसे 2002 गुजरात में चुनाव था, मेरी जिंदगी की वह सबसे बड़ी कसौटी थी, वैसे मेरे जीवन में मैने करीब करीब जितने चुनाव लड़े या लड़ाये उसमें मुझे जीतने का बहुत अवसर मिला है। मैंने टीवी तक नहीं देखा। रिजल्ट के समय भी नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगले के बाहर ढोल की आवाज आने लगी और मैंने लोगों को कहा कि 12:00 बजे तक मुझे कोई जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी की साहब आप दो तिहाई बहुमत से आगे चल रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था तो मेरे लिए ये अलग हो गया। उसी प्रकार से मेरे यहां एक बार पांच जगह पर बम ब्लास्ट हुए, आप कल्पना कर सकते हैं कैसी स्थिति होगी एक मुख्यमंत्री के नाते। मैंने कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम में जाना चाहता हूं तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि अस्पताल जाऊंगा। उन्होंने कहा कि साहब वहां भी बम फट रहे हैं। तो आप कह सकते है कि मुख्यमंत्री के नाते मेरे मन में कितनी बेचैनी या एंजायटी होगी। लेकिन, मेरा तरीका यह था कि मैं अपने मिशन के साथ खप जाता था, तो मैं उसको अलग रूप में अनुभव करता हूं शायद, मुझे उसमें जिम्मेदारी का भाव आ जाता है।

पीएम मोदी ने गोधरा मामले का जिक्र करते हुए कहा, मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 27 फरवरी पहली बार मैं विधानसभा में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतने बड़े कांड की खबर आने लगी ट्रेन में आग लगी है, धीरे-धीरे खबर आई। बहुत स्वाभाविक था कि मैं बेचैन था। मैंने हाउस से निकलते ही कहा गोधरा जाना चाहता हूं। यहां से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे तो बोले



हेलीकॉप्टर तो है नहीं, तो मैंने कहा किसी का देखो। ओएनजीसी का एक हेलिकॉप्टर था, जो सिंगल इंजन था। मुझसे कहा कि वीआईपी को इससे नहीं ले जा सकते। मैंने कहा कि वीआईपी नहीं हूं, कॉमन मैन हूं। फिर भी मना किया तो मैंने कहा कि मैं लिखकर देता हूं, कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद मैं गोधरा पहुंचा तो वहां का दर्दनाक दृश्य देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन, मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सबसे बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की।

दुनिया में भारत की बदलती अवधारणा पर

दुनियाभर में भारत की धारणा कैसे बदली है, इस पर पीएम मोदी ने उस दिन को याद किया जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब दुनिया भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़ी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से कहता था कि अगर एनआरआई भारत वापस नहीं आते हैं तो उनको पछतावा होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। सीएम पद पर रहते अमेरिका ने मुझे वीजा देने से इंकार कर दिया था। मैंने तब कहा था कि एक चुनी हुई सरकार के मुखिया के साथ ऐसा करना गलत और अलोकतांत्रिक है। मैंने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि एक दिन दुनिया भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़ी होगी। मैंने यह साल 2005 में कहा था। यह 2025 है, मैं देख सकता हूं कि यह भारत का समय है।

मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब समझाया

पीएम मोदी ने कहा, 'सरकार ने विभिन्न विभागों में काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए 40,000 कंप्लायंस हटा दिए हैं। हम अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब कम मंत्री और कम कर्मचारी हैं। हालांकि, यह मेरी समझ नहीं है। मैंने कौशल, सहकारिता और मत्स्य पालन के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनाए। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट कहता हूं तो इसे समझना होगा। 15,000 गैर जरूरी कानून खत्म कर दिए। वरना विभिन्न विभाग एक ही चीज की मांग करेंगे। अगर ये एक विभाग के पास है तो इसका उपयोग सभी के लिए हो। एक बार में ही काम हो।'

तकनीक के लोकतांत्रीकरण पर

पीएम मोदी ने कहा कि अब मैं सिर्फ 30 सेकंड में 100 मिलियन किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। मात्र 30 सेकंड में देश के 13 करोड़ लोगों के खातों में सिलेंडर सब्सिडी के पैसे भेज सकता हूं। भारत का यूपीआई दुनिया के लिए अजूबा है। भारत ने दुनिया को सिखाया है कि प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रीकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए बस आपको एक मोबाइल की जरूरत है। यह तकनीक से चलने वाली सदी है। सरकार ने एक इनोवेशन कमीशन और इनोवेशन फंड बनाया है।

भारत में दुनिया के बढ़ते भरोसे पर

युद्ध और दुनिया भर में चल रहे संघर्ष के मुद्दे पर अपने रुख पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम निष्पक्ष नहीं हैं। हम शांति के पक्षधर हैं। मौजूदा समय में संघर्ष कर रहे देशों को जो सलाह दी है, उससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। रूस और यूक्रेन के साथ भारत ने ईरान, फिलिस्तीन और इजरायल से भी यही कहा। ये देश भारत पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि भारत की साख बढ़ी है। दुनिया को हमारी बातों पर भरोसा है। ■



भारतीय रेल
आधुनिकता के रंग में सुगम यात्रा की प्रतीक

भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में गति के साथ-साथ भारतीय रेल आज दिल, समाज और लोगों को अवसर से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। विकसित भारत में विकसित रेलवे के योगदान को ध्यान में रखकर बीते एक दशक में रिकार्ड निवेश किया गया है। वंदे भारत, नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, सुरक्षित पटरी, सुविधायुक्त स्टेशन को तकनीक से जोड़कर रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 फरवरी 2019 को देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत' की शुरुआत की गई। छह वर्ष में ही करीब-करीब सभी राज्यों को वंदे भारत की कनेक्टिविटी मिल चुकी है। बीते एक दशक में रेलवे का परिदृश्य बदला है तो 2025 की शुरुआत से ही भारत ने रेल परियोजनाओं की व्यापक शुरुआत की है। इस शताब्दी के तीसरे दशक में रेलवे का कायाकल्प बन चुका है राष्ट्र का मिशन...



भारतीय रेल प्रतिदिन 2.3 करोड़ यात्रियों को कम खर्च पर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती है।

2,65,200
करोड़ रुपये है 2024-25 के लिए कुल पूंजी व्यय। यह अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है।

इस शताब्दी का यह तीसरा दशक, भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। बीते 10 साल में पूरी रेल का परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है तो इस तीसरे दशक के अंत तक यह नए आयाम स्थापित करेगा। भारत की ट्रेनें दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं रहेंगी। सुरक्षा, सुविधा, सफाई, सामंजस्य, संवेदना, सामर्थ्य, भारतीय रेल, पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी, इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। भारतीय रेल 100 फीसदी विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत की त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बनेगी।

आज देश में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। यानी यातायात के अलग-अलग माध्यमों को आपस

> **बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत लंबा सफर तय करना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक भारतीय रेल गरीब, मध्यम वर्ग, सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। मुझे विश्वास है, देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विकास गरीबी को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।**
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**



में जोड़ा जा रहा है। नमो भारत ट्रेन में भी मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। बीते 10 वर्षों में सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आज वह इसे आंखों के सामने होते हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक, वंदे भारत जैसी आधुनिक, सेमी-हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा, सुना, बोला तक नहीं गया था। एक दशक पहले तक, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक, नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक, विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक, ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, यह तो बहुत बड़ी बात मानी

> **इस शताब्दी का यह तीसरा दशक, भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते-मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं, उन्हें गारंटी देना चाहता हूं... इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। सुरक्षा, सुविधा, सफाई, सामंजस्य, संवेदना और सामर्थ्य में भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी।**
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**



वंदे भारत स्लीपर
सफर होगा आरामदायक

भारतीय रेल ने आधुनिक सवारी डिब्बे, उन्नत सुरक्षा फीचर और यात्री सुविधाओं वाली देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और मैन्युफैक्चर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू की है। इन ट्रेन की संख्या महज 6 वर्ष में 136 तक पहुंच गई है। 24 राज्यों के 333 जिलों को कवर कर चुकी है। वंदे भारत से अभी तक 4.2 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है।

लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत शयनयान यानी स्लीपर क्लास गाड़ियां चलाने की योजना पर भारतीय रेल काम कर रही है। ट्रायल के दौरान 180 किमी की रफ्तार से सुरक्षित पटरियों पर दौड़ चुकी है। वंदे भारत स्लीपर क्लास के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद 10 ट्रेन का उत्पादन भी किया जा रहा है। रेल कोच फैक्टरी, चेन्नई ने भी 50 वंदे भारत शयनयान का उत्पादन शुरू किया है।

136

वंदे भारत 24 राज्यों के 333 जिलों को कवर कर चुकी है



अतिरिक्त 200

वंदे भारत कोच की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारों को टेंडर आवंटित कर दिया गया है।

पूर्णतया गैर-वातानुकूलित अमृत भारत रेलगाड़ी

भारतीय रेल ने हाल ही में पूरी तरह से गैर-वातानुकूलित अमृत भारत रेलगाड़ी की शुरुआत की है। वर्ष 2024 में 4 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की गई हैं। इसमें 12 शयनयान सवारी डिब्बे और 8 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे हैं। वंदे भारत ट्रेनों के समान अत्याधुनिक तकनीक से परिपूर्ण यह ट्रेन शोर और झटका-मुक्त यात्रा का अनुभव देती है। यह प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम के साथ मॉड्यूलर शौचालय, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आदि जैसी आधुनिक संरक्षा और यात्री सुविधाओं से लैस है। शुरुआती बेड़े के सफल संचालन के बाद 50 अतिरिक्त अमृत भारत ट्रेनों के उत्पादन की योजना पर काम चल रहा है।

जाती थी। आज यह सभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक, मानवरहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी। बीते 10 वर्षों में 30 हजार किमी से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। आज सैकड़ों ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से बे-रोक-टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक, लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वालों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी सुविधा की अनुभूति कर पा रहे हैं।

भारतीय रेल को विश्व की आधुनिक परिवहन प्रणाली बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार चार मापदंडों पर काम कर रही है। **पहला-** रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। **दूसरा-** रेलवे के यात्रियों को किस तरह से आधुनिक सुविधाएं सुरक्षा के साथ सुगमता से मिले। **तीसरा-** देश के प्रत्येक कोने में रेलवे की कनेक्टिविटी स्थापित करना। इसी का परिणाम है कि आज जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई इलाके पहली बार रेलवे से जुड़ रहे हैं। **चौथा-** रेलवे से रोजगार का निर्माण और उद्योगों को सहयोग देना है। इन मापदंडों से आज रेलवे की पहुंच लगातार विस्तारित हो रही है।

आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक 'वंदे भारत'

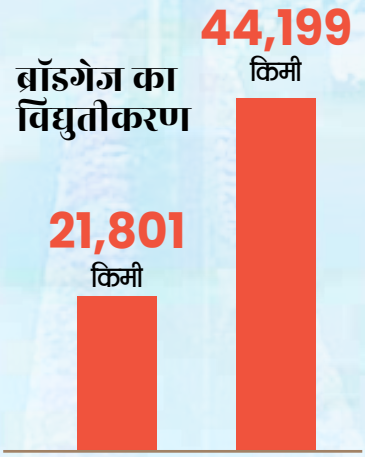
नए और तेजी से बदलते विकसित भारत के सपने को वंदे भारत ट्रेन एक नई गति दे रहा है। देखते-देखते स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन देश के मानचित्र पर तेजी से फैल रही है। आज 50 से अधिक रूट्स पर 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही है। भारत सरकार की तैयारी आने वाले वर्षों में वंदे भारत ट्रेन के रास्ते विश्व पटल पर छा जाने की है जिस पर रेल मंत्रालय ने काम भी शुरू कर दिया है। चारों दिशा में दौड़ती यह वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का ही नहीं बल्कि गुलामी की मानसिकता से निकल कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की भी प्रतीक बन रही है। यह उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर है। ऐसा भारत, जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। ऐसा भारत, जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है।

देश की आध्यात्मिक नगरी हो, आर्थिक नगरी हो या

नेट जीरो कार्बन लक्ष्य 2030

भारतीय रेल ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। नवंबर, 2024 तक लगभग 487 मेगावाट सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा - चौबीसों घंटे (आरई-आरटीसी) भी प्रवाहित होने लगी है। लगभग 2014 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है।

ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण



97%

ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है अब तक, 2014 तक 35 फीसदी हुआ था।

सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन

दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत ने बना लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन इंजन विकसित किया है, वह 1,200 हार्स पावर का है। दुनिया में अभी केवल चार देशों में हाइड्रोजन ट्रेन है जिनकी क्षमता 500-600 हार्स पावर है। इस तरह की पहली ट्रेन का जल्द ही हरियाणा में जींद-सोनीपत मार्ग पर ट्रायल रन किए जाने की उम्मीद है। भारत में निर्मित हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंजन को स्वदेशी टैलेंट का उपयोग कर विकसित किया गया है।



हाईटेक होंगे अमृत भारत स्टेशन

भारतीय रेल ने अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालीन दृष्टिकोण से रेलवे स्टेशनों का विकास शुरू किया है। यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन स्टेशनों के संपर्क मार्ग ठीक करने के साथ ही ऑपरेशन एरिया, जरूरत के हिसाब से लिफ्ट और एस्केलेटर, निशुल्क वाईफाई, एक स्टेशन-एक उत्पाद के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सुविधा प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज और कई तरह की सुविधाओं में सुधार का मास्टर प्लान तैयार करना और उसे मूर्त रूप देना योजना में शामिल है। देशभर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से रोजगार सृजन में वृद्धि तथा आर्थिक विकास में सुधार के साथ अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2,000 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से पूर्ण है।

1,337

स्टेशन को योजना के लिए दिसंबर, 2024 तक चिन्हित किया गया है, जिनमें से करीब 1,200 स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है।

मालगाड़ी के लिए दो फ्रेट कॉरिडोर

भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों के लिए दो समर्पित कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया है। लुधियाना से सोननगर (1,387 किमी) पूर्वी माल समर्पित कॉरिडोर और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट टर्मिनल से दादरी (1,506 किमी) पश्चिमी कॉरिडोर के 2,843 किलोमीटर में से 2,741 किलोमीटर(96.4 फीसदी) कॉरिडोर पर परिचालन शुरू कर दिया गया है।



83,343
मालगाड़ी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस समर्पित कॉरिडोर पर चलाई गईं हैं।



रफ्तार के नए शिखर पर भारतीय रेल



पौराणिक शहर हो, सभी शहरों में वंदे भारत कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है ताकि व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ पर्यटन, विरासत और संस्कृति को भी संजोया जा सके। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी। स्वदेश निर्मित वंदे भारत ट्रेन देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से समय की बचत होती है और देश में विकास की गति भी तेज होती है। यही कारण है कि नए जलमार्ग, वाटरवेज के साथ हवाई संपर्क के जरिए शहरों को जोड़ने का काम देश में बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। इससे यातायात में सुगमता, समय की बचत और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

बदलते हुए भारत में यह बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो। लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े-करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हों, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हों, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। साथ ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो आज भारत जितना खर्च कर रहा है, उतना देश में पहले कभी नहीं हुआ। आत्मविश्वास से भरे इस माहौल के बीच, अमृत काल का भारत, अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक में सभी हितधारकों में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। रेलवे की जरूरत के अनुरूप कौशल को ध्यान में रखते हुए देश का पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है।

देश में परिवहन का खर्च कम हो, निर्यात की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक्स नीति लागू की गई है। देश में परिवहन का एक माध्यम, दूसरे को सहयोग करे, इसके लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। प्रति घंटे 160 किमी गति वाली यह वंदे भारत ट्रेन इसी भावना की प्रतिबिंब हैं। केवल यात्रियों के लिए ही ट्रेनों की गति नहीं बढ़ी है, बल्कि भारतीय जनमानस में मालगाड़ियों को लेकर आम धारणा रही है कि इसके चलने और गंतव्य तक पहुंचने का कोई समय नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस अवधारणा को बदला है। औसत 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ी भी अब 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही है।

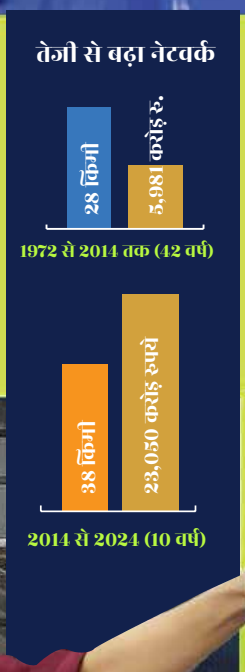
हाई स्पीड बुलेट रेल के लिए समुद्र के नीचे सुरंग बननी शुरू

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (508 किमी) भारत में हाई स्पीड रेल की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है, जिस पर जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से काम किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। दिसंबर, 2024 तक 368 किमी पियर फाउंडेशन, 346 किमी पियर निर्माण, 234 किमी गर्डर लॉन्चिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कॉरिडोर पर समुद्र के नीचे लगभग 21 किलोमीटर की सुरंग बनाई जानी है, जिसका काम शुरू कर दिया गया है।

कोलकाता में दौड़ी अंडर वाटर मेट्रो रेल

देश में पहली बार कोलकाता के एस्प्लानेड से हावड़ा मैदान के बीच चलने वाली मेट्रो लाइन पर जब ट्रेन हुगली नदी के नीचे से गुजरी तब एक नया इतिहास रचा गया। पीएम मोदी ने 2024 में पहली अंडर-वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। यह देश की पहली मेट्रो रेल है जो किसी नदी के नीचे बनी सुरंग में होकर गुजरती है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे अधिक गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन है।

- कोलकाता में मेट्रो परियोजना की शुरुआत 1972 में हुई थी।
- 66 किमी मेट्रो लाइन का निर्माण हो चुका है।
- कोलकाता और आसपास 59 किमी मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है।



ईज ऑफ ट्रैवल के लिए स्पीड और स्केल

भारतीय रेलवे का जिस तरह से कायाकल्प हो रहा है, वह नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे-छोटे सपने देखने छोड़ दिए हैं। विकसित भारत के लिए विकसित रेलवे का संकल्प यथार्थ हो रहा है। फरवरी 2024 में एक साथ रेलवे से जुड़ी 2,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था। तब 27 राज्यों के, करीब 300 से अधिक जिलों में, 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ। यह दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है।

अमृत-भारत स्टेशन, विरासत और विकास, दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है। सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन, 16वीं शताब्दी की हैंड-ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल की वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका का स्टेशन, द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन, आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन, उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएंगे। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांग और बुजुर्गों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा लेकिन अब भारतीय रेलवे, देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल यानी सुगम यात्रा का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। यह सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। 10 साल पहले जब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, तब रेलवे का औसत बजट 45 हजार करोड़ रुपये के आसपास रहता था। आज जब देश 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है तो रेल बजट ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। ऐसे में यह कल्पना की जा सकती है कि जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा तो देश का सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। बीते 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और सरकारी पैसे की लूट को बचाया गया है। इसलिए नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हुई। आज जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक, ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है, जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ, तभी ढाई हजार किलोमीटर से अधिक के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई-पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब-करीब 50 प्रतिशत तक की छूट देती है।

किसान रेल

बाजारों तक आसान होगी पहुंच

अगस्त, 2020 में किसान रेल सेवा के शुरू किए जाने के बाद से रेलवे ने 2,364 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया। इस सेवा ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से लगभग 7.9 लाख टन वस्तुओं की ढुलाई की है। रेलवे ने इसमें करीब 154 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।



एक स्टेशन-एक उत्पाद

कारीगरों को मिला नया बाजार

भारतीय रेलवे ने 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' योजना प्रायोगिक तौर पर शुरू की थी, जिसे धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना में रेलवे स्टेशनों पर बिक्री केंद्रों के माध्यम से स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और बिक्री के लिए स्थानीय दस्तकार, कुम्हार, बुनकर एवं शिल्पकारों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जाता है।

- देश में 1,906 स्टेशन पर 2,170 बिक्री केंद्र चालू किए गए हैं। इस योजना का 83 हजार से अधिक लाभार्थियों ने लाभ उठाया है।

भारत गौरव ट्रेन

सांस्कृतिक विरासत का कराएगी दर्शन

भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ियां थीम-आधारित पर्यटक सर्किट रेलगाड़ियां हैं जिनका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों का प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था। अकेले 2024 में ही 158 ट्रिप में भारत गौरव ट्रेनों के जरिए 1,04,077 लोग यात्रा कर चुके हैं।

सबसे छोटा भाप इंजन

1881 में निर्मित सबसे छोटा भाप इंजन 'बेबी सिवोक' अब भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन (घूम स्टेशन) पर प्रदर्शित किया गया है, जो पर्यटकों को रेलवे की समृद्ध विरासत के साथ एक ठोस जुड़ाव प्रदान करता है।





709.5

करोड़ यात्रियों ने 2013-14 से 2023-24 के बीच आरक्षित श्रेणी और 6,863 करोड़ यात्रियों ने अनारक्षित श्रेणी में यात्रा की है।

हर यात्री को 46% किराए में छूट

रेलवे सभी यात्रियों को किराए में 46 फीसदी सब्सिडी देता है। भारतीय रेलवे के अनुसार 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। यह रेल से यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली औसत 46 फीसदी सब्सिडी के बराबर है। आसानी से समझने के लिए इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये होती है तो टिकट की कीमत 54 रुपये है।

हेरिटेज रेलवे स्टेशन

उत्तर रेलवे के अंतर्गत वर्ष 1882 में बने काशी रेलवे स्टेशन को हेरिटेज रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया है।



यात्रियों की सुगमता-सुरक्षा प्राथमिकता

भारतीय रेलवे, देश के गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। भारत में एक दिन में जितने लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। यह दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। अब केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था, अब 8 गुना से ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेन चलाना हो, नए रूट का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है।

भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता-पिता, बच्चे, दादा-दादी, नाना-नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? लेकिन बीते एक दशक में यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक समग्र सोच के साथ रेलवे का विकास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगह से यात्रा करके आता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वह व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वह घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वह बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है। टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए रेलवे के हर कर्मचारी को, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए, लगातार संवेदनशील रहना होता है।

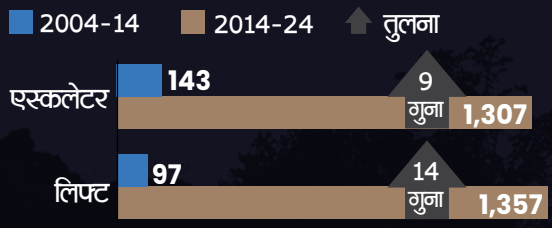
दोगुनी गति से बिछाई जा रही नई रेल पटरी

2009-14	2014-24
7,599 किमी	31,180 किमी

इस तरह बदली तस्वीर

	2004-14	2014-24	तुलना
रेलवे ट्रैक नवीकरण पर खर्च	47,038	1,09,577	2.33 गुना
नए जोड़े गए रेलवे ट्रैक (किमी)	14,985	31,180	2.08 गुना
मानव रहित फाटक	8,948 (2014)	शून्य (2019)	100% कमी
मानवयुक्त फाटक समाप्त	1,137	7,075	6.21 गुना
फॉग पास सेफ्टी डिवाइस	90 (2014)	19,742	219 गुना
रेलवे में की गई भर्तियां	4.11 लाख	5.02 लाख	20% से अधिक

14 गुना लगाई गई रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट



अमृत काल में रेलवे की नई पहचान

भारतीय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन, चलता फिरता घर होती है तो रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थाई घर जैसे ही होते हैं। देश में हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया था। विकसित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण का अभियान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर का निर्माण हो रहा है। कुछ समय पूर्व ही देश के 1,000 से ज्यादा बड़े स्टेशनों के पुनर्विकास का काम शुरू किया गया है। अमृत काल में बने यह नए स्टेशन अमृत

रेलवे सेफ्टी के लिए किए गए उपाय

ट्रैक नवीकरण और संरक्षा पर निवेश के लिए बजट

2024-25 — 1,08,776 करोड़ रुपये

2023-24 — 1,01,650 करोड़ रुपये

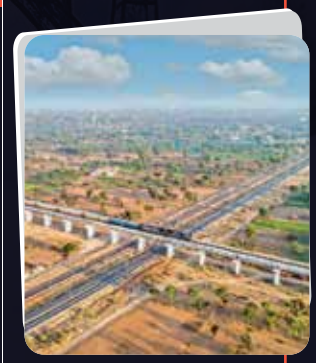
सुरक्षा अब प्राथमिकता



रेल ऑपरेशन में संरक्षा दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक दुर्घटना प्रति मिलियन रेलगाड़ी किलोमीटर की बात करें तो 2014-15 में 0.11 से घटकर 2023-24 में 0.03 रह गया है। यह 73 फीसदी से अधिक सुधार है।

11,082 लेवल क्रॉसिंग यानी फाटक पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई।

- मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 6,600 से अधिक स्टेशन पर केंद्रीकृत परिचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई।
- लोको पॉयलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेल इंजन में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।
- मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है, ताकि कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके।
- कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस की व्यवस्था की जाती है, ताकि लोको पायलट को रास्ते में आने वाले मुख्य स्थल, सिग्नल व रेल फाटक की दूरी का पता चल सके।
- रेलवे ट्रैक नवीकरण तेज गति से करने और बेल्डिंग से बचने के लिए 130 और 260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति बढ़ाई गई है।
- रेल पटरियों में आने वाली दिक्कतों का पता लगाने और खराब पटरियों को बदलने के लिए रेल की अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन परीक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल से लेकर महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी तक 6.31 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।



10 वर्षों में 12,000 ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण किया गया है। यह उपलब्धि बढ़ी हुई सुरक्षा और कुशल ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करती है, जो रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।





भारत स्टेशन कहे जाएंगे। यह स्टेशन आने वाले दिनों में, नए भारत की पहचान बनेंगे।

अमृतकाल में देश ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य का, हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था, तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा, उसी राज्य में ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। उसमें भी होता ये था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थीं लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थीं। इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। देश के लोगों का नुकसान किया। अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। अब सबका साथ सबका विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ते रहने की सोच रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है।

औद्योगिक प्रगति का वाहक बनता रेलवे

भारतीय रेल यात्री की सुविधा ही नहीं बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी, ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इससे उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "मुझे छोटे-छोटे सपने देखने और धीमे चलने की आदत नहीं है। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं कि इस दशक के अंत तक, आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे।" केंद्र सरकार के प्रयासों से भारतीय रेल सुरक्षा, स्वच्छता, सुविधाओं, समन्वय, संवेदनशीलता और क्षमता में दुनिया में नया मुकाम हासिल कर रही है। भारतीय रेल 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य के समीप है। नमो भारत और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अमृत भारत



एलएचबी कोच का निर्माण एक दशक में पहुंचा 16 गुना

अवधि 2004-14	अवधि 2014-24
2,337	36,933

पिछले एक दशक में तीन गुना बने आरयूबी-आरओबी





विदेशी पर्यटकों को सुविधा

विदेशी पर्यटकों को कंफर्म आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करते हुए ऑनलाइन 365 दिन पहले आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- रेल यात्रियों को चार्ट तैयार होने तक अब ट्रेन में चढ़ने का स्थान ऑनलाइन बदलने का विकल्प दिया गया है।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारतीय रेल का हर कोच अब जैव शौचालय युक्त है।









सामान्य श्रेणी में अधिक सुविधा

मौजूदा नीति के अनुसार मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ी की संरचना में 22 डिब्बे वाली गाड़ी में 12 डिब्बे सामान्य श्रेणी व गैर वातानुकूलित शयनयान श्रेणी और 8 वातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रावधान है। इससे सामान्य श्रेणी और गैर वातानुकूलित शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा होती है।

- होली और गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन के 13,523 फेरे लगाकर वर्ष 2024 में सीटें उपलब्ध कराई।
- दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2024 के बीच स्पेशल रेलगाड़ियों ने 7,990 फेरे लगाए जिससे 1.8 करोड़ यात्रियों को लाभ हुआ।
- अनारक्षित श्रेणी के डिब्बों की संख्या और सुविधा बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष में नवंबर 2024 तक एलएचबी सवारी डिब्बों के साथ चलने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में 900 से अधिक डिब्बे जोड़े गए हैं।
- रेलवे 2018 से आधुनिक एलएचबी कोच का निर्माण कर रही है। अभी तक 75 जोड़ी से अधिक ट्रेनों को आधुनिक एलएचबी कोच वाली ट्रेन में परिवर्तित किया गया है।
- बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने सामान्य श्रेणी और शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित 10,000 गैर वातानुकूलित सवारी डिब्बों की मैन्युफैक्चरिंग की योजना बनाई है। पिछले पांच वर्ष के दौरान विभिन्न सेवा में विभिन्न श्रेणी के लगभग 5,200 सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं, जिनमें 1,100 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे शामिल हैं।
- वर्ष 2014 से पहले, सीसीटीवी निगरानी सुविधाओं से लैस स्टेशनों की संख्या 123 थी, बीते एक दशक में 800 से अधिक स्टेशन पर सीसीटीवी लगाए गए।

6,000

से अधिक स्टेशन पर वाई-फाई की सुविधा शुरू की जा चुकी है।



दुनिया में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन का भारतीय रेल नेटवर्क

- भारत के पास दुनिया के अन्य रेल नेटवर्क की तुलना में सबसे अधिक 7,325 स्टेशन हैं।
- दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक भारत में पिछले 10 वर्ष में बिछाए गए हैं।
- भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण जब पूरा कर लेगा तब दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेल नेटवर्क बन जाएगा।



जम्मू बना रेलवे का नया डिवीजन

भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के अधीन जम्मू में एक नया रेलवे मंडल स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी, 2025 को किया। जम्मू मंडल का मुख्यालय जम्मू शहर को बनाया गया है जो भारत को सुदूर उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह मंडल जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों की रेल परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नया मंडल उत्तर रेलवे के मौजूदा फिरोजपुर मंडल को विभाजित करके बनाया गया है। नए मंडल के अधिकार क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण गुड्स शेड/गुड्स टर्मिनल शामिल हैं जो खाद्यान्न, पेट्रोलियम, सीमेंट, चीनी, कोयला, उर्वरक, मौसमी फल और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होंगे। इस मंडल में 3 गतिशक्ति कार्गो प्वाइंट हैं। एक माल ढुलाई प्रबंधन टर्मिनल जम्मू के समीप बाड़ी ब्राह्म में बनाया जा रहा है। कश्मीर क्षेत्र में तीन गुड्स शेड बनाने की भी योजना है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का काम पूरा

जम्मू-कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली देने के लिए भारत सरकार ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना (यूएसबीआरएल) के तहत उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना बनाई थी जो कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ेगी। इस परियोजना के अंतर्गत सबसे कठिन और अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी इलाकों में रेलवे लाइन बिछाई गई है जिसमें बड़ी संख्या में सुरंग और पुलों का निर्माण किया गया है। इस रेल लिंक का कार्य पूरा हो गया है। अब जल्द ही कन्याकुमारी से सीधे कश्मीर तक रेल सफर की शुरुआत हो जाएगी।

- **उधमपुर-कटड़ा (25 किमी)** : जुलाई 2014 में इसे चालू किया गया।
- **बनिहाल-काजीगुंड (18 किमी)** : जून 2013 में काम पूरा और सेक्शन चालू हो गया। इसमें 11.2 किमी की टी-80 पीर पंजाल सुरंग भी शामिल है।
- **काजीगुंड-बारामुला (118 किमी)** : कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा हुआ। सेक्शन चालू हो गया, जिसका अंतिम भाग 2009 में खोला गया।
- **कटड़ा-बनिहाल (111 किमी)** : बनिहाल-संगलदान (48 किमी) राष्ट्र को समर्पित, रियासी-सांगदान (46 किमी) 20 फरवरी 2024 को काम पूरा हुआ और एक जलाई 2024 को रेलवे सेफ्टी कमिश्नर से प्रमाणन प्राप्त हो गया है।
- **कटरा-रियासी (17 किमी)** : कार्य पूर्ण और सीआरएस प्रमाणन प्राप्त।

रेलवे स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने जैसी पहलों को सूचीबद्ध किया गया है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बनने वाली है।

विकसित होते भारत के लिए विकसित रेल

विकसित होते भारत के लिए रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण जरूरी है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली बार रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण का अभियान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकार्ड संख्या में फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर का निर्माण किया जा रहा है। देश भर में 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। देश के 500 से ज्यादा बड़े रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम शुरू भी कर दिया गया है। 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है जिन्हें अमृत भारत स्टेशन



अंजी खड्ड पुल और चिनाब इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण

अंजी खड्ड पुल : भारतीय रेल का पहला केबल आधारित पुल है। इसमें 96 केबल का उपयोग किया गया है जिसका वजन 849 मिट्रिक टन है। अंजी पुल का निर्माण भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण उधमुपर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में किया गया है। यह पुल हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है जो दुर्गम पहाड़ियों और प्राकृतिक जटिलताओं व भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है।



अंजी खड्ड पर मुख्य पुल 473.25 मीटर की कुल लंबाई वाला एक केबल आधारित ब्रिज है, जिसका मुख्य स्पैन 290 मीटर का है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटड़ा-बनिहाल सेक्शन पर अंजी खड्ड पुल सुरंग टी-2 और टी-3 को जोड़ता है। अंजी खड्ड पुल में नींव के शीर्ष से 193 मीटर ऊंचा एक मुख्य पायलन है जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पुल को 213 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले भारी तूफान को झेलने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसके डेक पर 40 किलोग्राम विस्फोटक से भी विस्फोट किया जाता है तो पुल को क्षति नहीं पहुंचेगी।

चिनाब पुल : जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक मेहराबदार पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसके निर्माण पर 1,486 करोड़ रुपये की लागत आई है। पुल की लंबाई 1,315 मीटर है और नदी के तल से डेक की ऊंचाई 359 मीटर है। पुल की डिजाइन अवधि 120 वर्ष है। पुल के निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन इस्पात इस्तेमाल किया गया है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चलेगी तो पुल को किसी तरह का नुकसान या ट्रेनों की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी।

ओडिशा में चल रही 70,000 करोड़ रु. से अधिक की रेलवे परियोजनाएं

पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी, 2025 को ओडिशा के रायगढ़ रेलवे मंडल की आधारशिला रखी। इससे जहां राज्य के रेलवे इंफ्रास्टक्चर को मजबूती मिलेगी तो वहीं दक्षिण ओडिशा में पर्यटन, व्यवसाय और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। ओडिशा में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और विशाल समुद्र तट है। इसके चलते यहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। राज्य में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं।

तेलंगाना के चरलापल्ली में नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन

पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में चरलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह टर्मिनल आउटर रिंग रोड से जुड़कर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी। आउटर रिंग रोड से जुड़ा यह स्टेशन, क्षेत्र में विकास को काफी बढ़ावा देगा। स्टेशन के प्लेटफार्म पर लिफ्ट, एस्केलेटर, सौर ऊर्जा से संचालित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नया टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुडा के मौजूदा स्टेशनों पर भीड़भाड़ का दबाव कम करेगा जिससे लोगों की यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।





का नाम दिया गया है। देश के पूर्वी हिस्से सहित संपूर्ण भारत में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। 2014 से पहले देश में 6 हजार से भी कम रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज थे लेकिन अब इसकी संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। बड़ी लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की संख्या अब शून्य हो गई है। जल्द ही 100 प्रतिशत रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। जबकि 2014 से पहले बामुश्किल 35 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था। वर्ष 2030 तक भारत, एक ऐसा देश होगा जिसका रेलवे नेटवर्क शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर चलेगा।

बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी और परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही, देश में रेल कोच फैक्टरियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन कछुआ चाल से चलती थी लेकिन आज एक मिनट में 20 हजार से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने में कम से कम दो साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट तीन-चार या ज्यादा से ज्यादा छह महीने में स्वीकृत हो जाती है। ऐसे ही प्रयास से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉड गेज की लाइनों से मानव रहित क्रासिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। जबकि 2014 से पूर्व देश में 8 हजार 300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रासिंग थीं जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते थे लेकिन अब ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित रेल के क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं।

देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम, पहले से दोगुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों से प्रदूषण भी कम हो रहा है, डीजल का खर्च भी बच रहा है

राष्ट्रीय स्वचालित रेलगाड़ी रक्षण- कवच

कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। यह प्रणाली ट्रेन की रफ्तार की लगातार निगरानी करती है और स्वचालित रूप से स्वीकार्य गति सीमा का अनुपालन करती है। यदि ट्रेन की रफ्तार स्वीकार्य गति सीमा से अधिक हो या वह विशिष्ट सिग्नल पहलुओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो एटीपी तुरंत ट्रेन को रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक को सक्रिय कर देती है। कवच को जुलाई, 2020 में अपनाया गया। कवच दक्षिण मध्य रेल और उत्तर मध्य रेलवे के 1,548 मार्ग किलोमीटर में लगाया जा चुका है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर (करीब 3,000 किमी) पर कार्य प्रगति पर है। 15,000 रूट किलोमीटर (आरकेएम) के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं।

10,000
लोको को कवच सुरक्षा तकनीक से लैस किया जा रहा है।

9,000
तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया गया।

भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने वाली - प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस

भारतीय रेल ने एक विशेष प्रवासी भारतीय ट्रेन की शुरूआत की। इस ट्रेन में करीब 150 लोग पर्यटन और आस्था से जुड़े गंतव्य स्थलों का भ्रमण करेंगे। यह ट्रेन में 45 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के भारतीय मूल के निवासियों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रस्तुत करती है। तीन सप्ताह की इस यात्रा में यात्री अयोध्या, वाराणसी, पटना, गया, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै, कोच्चि, गोवा, एकता नगर, पुष्कर, अजमेर और आगरा जैसे जगहों पर जाएंगे। हर पड़ाव पर उन्हें भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध परंपराओं का अनुभव मिलेगा।

27
देश

150
यात्री

14
स्थलों की यात्रा





12,00,000
के करीब कर्मचारी/ अधिकारी भारतीय रेलवे में कार्यरत

2,037
हैं लोको पायलट

1,00,000
महिला कर्मचारी हैं भारतीय रेलवे में कार्यरत

सुरेखा यादव हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट

बजट अनुमान 2024-25

रेलवे के लिए कुल पूंजीगत व्यय 2,65,200 करोड़ रुपये है जिसमें सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपये है।

1.92
लाख करोड़ रुपये जनवरी, 2025 के पहले सप्ताह तक खर्च किए।

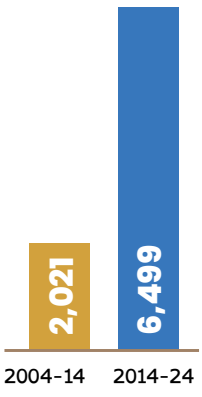
सुरक्षा

34,412 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 28,281 करोड़ रुपये सुरक्षा संबंधी कार्यों में खर्च किए गए जो आवंटित राशि का 82% है।

रोलिंग स्टॉक

बजटीय प्रावधान 50,903 करोड़ रुपये का था जिसमें से 40,367 करोड़ रुपये खर्च किए गए, खर्च 79% है।

3 गुना से ज्यादा इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन



> **नार्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है।**
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

और ट्रेनों की गति भी बढ़ी है। जाहिर है, रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों से रोजगार के नए अवसर भी बने हैं।

जब बनी दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क बनाने की सोच

21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए दृष्टिकोण के साथ भले काम कर रहा है। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भारत को एक बना-बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहतीं तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थीं लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोकलुभावन वादों के लिए, रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। सही अर्थों में रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब ये तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी-ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं करवाईं, जो कभी चली ही नहीं। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था।



जब 2014 में देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ तो उसके नेतृत्व ने यह तय किया कि अब रेलवे का कायाकल्प होकर रहेगा। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने? साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या-क्या खबरें आती थीं, सभी जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह-जगह, हजारों मानवरहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थीं। कभी-कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थीं। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क, मानवरहित

पूर्वोत्तर में बढ़ी रेल कनेक्टिविटी

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2014 के पहले असम का गुवाहाटी ही सिर्फ रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। 'कैपिटल कनेक्टिविटी' प्रोजेक्ट के तहत अब ईटानगर-अरुणाचल और त्रिपुरा का अगरतला भी इससे जुड़ गया है। वर्ष 2022 में पहली बार मणिपुर के तमेंगलोंग स्थित रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मेघालय पहुंची। बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली अगरतला-अखौरा रेलवे परियोजना से कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई। नगालैंड को 100 वर्ष बाद अपना दूसरा स्टेशन मिला है। क्षेत्र में नई रेलवे लाइनों की कमीशनिंग में तीन गुना वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों व शेष भारत के साथ रेल संपर्क में सुधार करने के लिए 1,368 किलोमीटर की 18 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (13 नई लाइन और 5 दोहरीकरण) वह प्लानिंग, अनुमोदन या निर्माण के अलग-अलग चरण में हैं। यह करीब 75 हजार करोड़ रुपये की लागत के हैं। प्रोजेक्ट पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं। इनमें से 313 किलोमीटर लंबाई चालू की जा चुकी है। मार्च, 2024 तक इन पर करीब 41 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो करीब 1,700 किलोमीटर से अधिक के खंड को नई लाइन, परिवर्तन गेज या दोहरीकरण किया गया। इस दस वर्ष में प्रति वर्ष औसतन 173 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए जबकि 2009-14 के दौरान यह आंकड़ा केवल 67 किलोमीटर प्रति वर्ष था यानी पिछले एक दशक में 170% अधिक नए ट्रैक बनाए गए हैं। इतना ही नहीं पिछले एक दशक में प्रति वर्ष औसतन 142 किलोमीटर पटरियों का विद्युतीकरण किया गया जो 2009-14 के दौरान शून्य था। इसी अवधि के दौरान 470 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण क्षेत्र में किया गया। भारतीय रेल को पूंजीगत व्यय के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 में जो 2.62 लाख करोड़ रुपये मिले हैं उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10,376 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो 2009-14 की अवधि के दौरान वार्षिक औसत बजट परिव्यय से 5 गुना अधिक है। इससे पूर्व 1,368 किलोमीटर की नई पटरियों से जुड़ी 18 चालू परियोजनाओं के लिए पहले ही 74,972 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।



महाकुम्भ

रेलवे की 13 हजार नियमित/विशेष ट्रेन

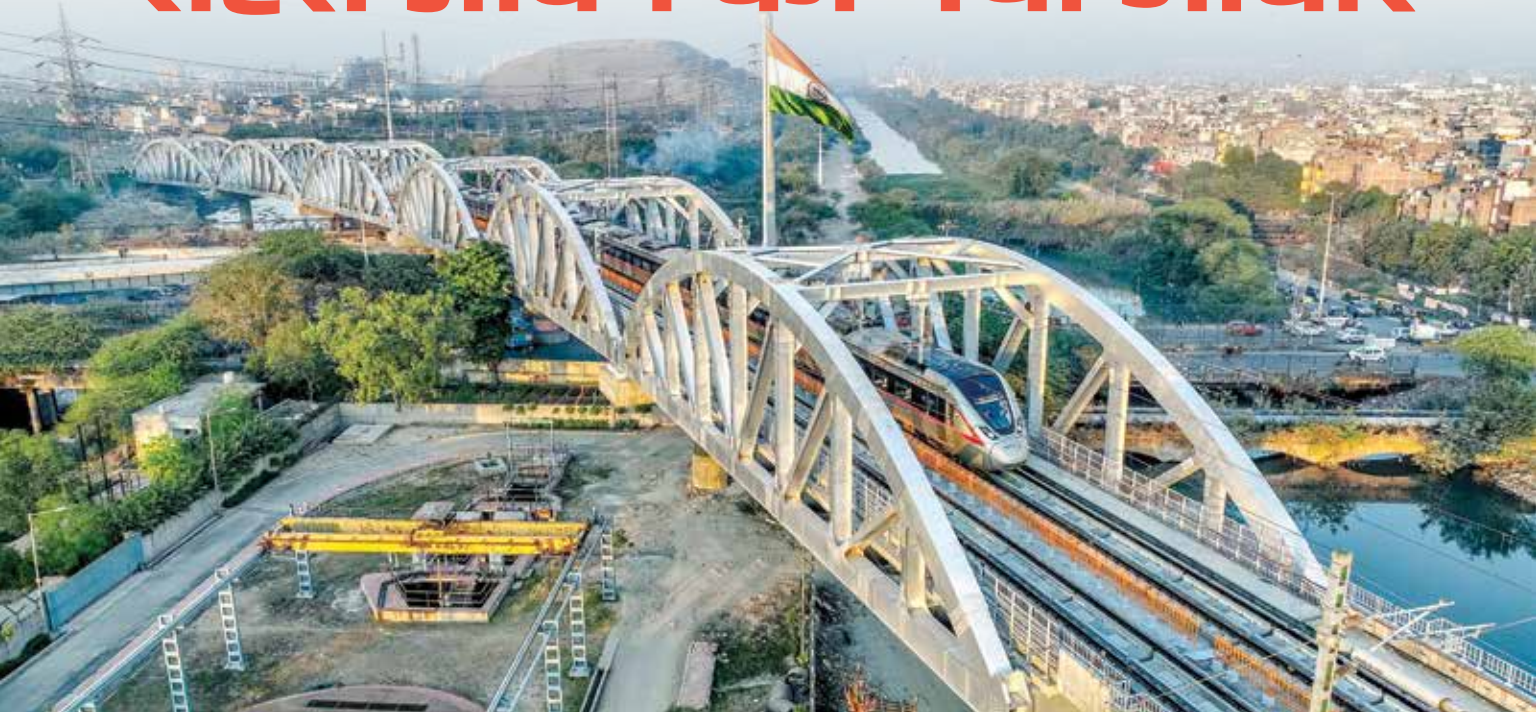
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया है कि महाकुम्भ में अनुमानित यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखकर 10,000 नियमित सहित 13 हजार ट्रेन चलाने का पूरा खाका पहले ही बना लिया गया था। यह मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सेवा के लिए एक केंद्रित प्रयास को दर्शाता है।

फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने और जान-माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन होती रहती थी। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आया तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी, भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है।

निश्चित रूप से आज उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश की विकास यात्रा में रेलवे नित नए अध्याय जोड़ रहा है। बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है लेकिन अभी इस दिशा में बहुत लंबा सफर तय करना है। केंद्र सरकार इस बात को लेकर संकल्पित है कि तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक भारतीय रेल गरीब, मध्यम वर्ग, सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। ■

भारत में जल्द होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क

मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल
शहरी जीवन का नया आधार



तेज गति और बड़े बदलाव नए भारत की पहचान बन चुके हैं। योजना बनाना हो या उसे लागू करना। देश अब नई स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। इसी का परिणाम है कि 2014 तक जो भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं था, वह आज दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है। जल्द ही इस मामले में हम दूसरे पायदान पर होंगे। मेट्रो के बाद अब वाटर मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल से मिला है शहरी जीवन को नया आधार...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो विकास की गति भी तेज होगी। बीते एक दशक में मेट्रो नेटवर्क के निर्माण की गति इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। इस दौरान देश में करीब 750 किमी से ज्यादा नया मेट्रो नेटवर्क तैयार किया गया है जो 2014 तक महज 248 किमी था। वहीं, एक दशक में ही देश के 5 शहरों से बढ़कर मेट्रो अब 13 राज्यों के 23 शहरों में तेज और सुरक्षित यात्रा का सबसे विश्वसनीय माध्यम बनी है। करीब एक करोड़ लोग इसमें रोजाना यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा।

मेट्रो के साथ केंद्र सरकार ने हाई स्पीड कनेक्टिविटी की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए रैपिड रेल सेवा भी शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च, 2019 को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई के बीच



शीर्ष तीन मेट्रो नेटवर्क वाले देश

चीन	4,201 किमी
यूनाइटेड स्टेट्स	1,408 किमी
भारत	1,000+किमी

भारत में चालू मेट्रो नेटवर्क

2014	248 किमी	5 शहर
2024	1,000 किमी	23 शहर

1,000 किमी से अधिक नए मेट्रो रूट पर तेजी से चल रहा है देश में काम।

प्रतिदिन औसत यात्री

01 करोड़ + (2024)

26 लाख (2013-14)



हर महीने जुड़ा रहा है नया 6 किमी मेट्रो नेटवर्क

2014 से पहले — 600 मीटर



2024 — 6 किमी



कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऐतिहासिक मार्ग पर सवारी की, जिससे सार्वजनिक परिवहन में एक नया युग शुरू हुआ।





कोच्चि वाटर मेट्रो बनी भारत की शान

केरल का कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला शहर है। यह शहर के आसपास के 10 द्वीपों को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नावों से जोड़ती है। यहां दिसंबर, 2021 में पहली नाव शुरू की गई थी। इसके बाद अप्रैल, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी शुरुआत 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं के साथ की गई, जिन्हें 78 तक बढ़ाया जाएगा। यह पूरा सिस्टम मेट्रो नेटवर्क की तरह काम करता है। कोच्चि मेट्रो के टोकन पर ही लोग इसमें भी यात्रा कर सकते हैं।

मेट्रो यात्रा का भविष्य स्वदेशी है

1,000 से अधिक मेट्रो कोच का उत्पादन 5 वर्ष में

पहला मेक इन इंडिया चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंपा गया

भारत में निर्मित मेट्रो, विश्व के लिए तैयार

- दिल्ली मेट्रो बांग्लादेश में मेट्रो रेल प्रणाली का निर्माण कर रही है।
- जकार्ता में परामर्श सेवाएं प्रदान की।
- कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच का निर्यात किया।

जून, 2025 के तय समय से पहले ही इस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर के खंड का निर्माण भी पूरा कर लिया गया। यहां 20 अक्टूबर, 2023 को देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। इस सेक्शन पर 17 किलोमीटर की दूरी महज 12 मिनट में तय हो रही है। दिसंबर, 2024 तक साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण के बीच 42 किलोमीटर में नमो भारत रैपिड रेल शुरू कर दी गई। जनवरी, 2025 में 13 किलोमीटर का कॉरिडोर और जुड़ गया। अब रैपिड रेल 55 किलोमीटर में फैले 11 स्टेशन को कवर करने के साथ ही देश की राजधानी से भी सीधे जुड़ गई है। दिल्ली के न्यू अशोक

देश के इन शहरों में मिल रही है मेट्रो रेल की सवारी

शहर	मेट्रो चालू (किमी)	निर्माणाधीन मेट्रो रेल नेटवर्क (किमी)
दिल्ली व एनसीआर के शहर	रैपिड रेल शामिल 435	155
बैंगलुरु	77	140
हैदराबाद	69	-
कोलकाता	58	175
चेन्नई	54	119
जयपुर	12	-
कोच्चि	28	11
लखनऊ	23	-
कानपुर	9	24
आगरा	6	24
नागपुर	40	44
पुणे	33	33
मुंबई	90	176
ठाणे	-	29
अहमदाबाद/ गांधी नगर	59	9
सूरत	-	40
भोपाल	-	28
इंदौर	-	32
पटना	-	32



चालक रहित मेट्रो: भारत ने दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर 28 दिसंबर 2020 को अपनी पहली चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू की।



मेट्रो रेल का पहला नेटवर्क दो दशक में वास्तविकता में बदला

1969 भारत में मेट्रो सिस्टम के लिए पहल मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से शुरू की गई थी।

1984 पहली मेट्रो ने कोलकाता के एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच 3.4 किलोमीटर की दूरी तय की।

1995 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की स्थापना दिल्ली में विश्व स्तरीय मास रैपिड ट्रांसपोर्ट लाने के लिए की गई।

2002 डीएमआरसी ने दिल्ली में शाहदरा और तीस हजारी के बीच अपना पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू किया। देश के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक के लिए मंच तैयार हुआ।

2011 नम्मा मेट्रो (बेंगलुरु मेट्रो) का पहला खंड बनाया गया।

2017 चेन्नई मेट्रो का विस्तार ग्रीन लाइन कोयम्बेडु से नेहरू पार्क तक के खंड के उद्घाटन के साथ हुआ जो दक्षिण भारत के मेट्रो विकास के लिए एक मील का पत्थर है।

2020 कोच्चि मेट्रो का पहला चरण पूरा। थायकुडम-पेट्टा खंड चालू होने के साथ ही केरल भारत में बढ़ते मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा बन गया।

नगर से मेरठ दक्षिण तक 55 किलोमीटर की दूरी महज 40 मिनट में तय हो रही है। इस सेक्शन पर हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध है। इस सेक्शन पर शुरू से अंत तक यात्रा करनी है तो स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपये और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपये चुकाने होंगे। नए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने की प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना के अनुरूप रैपिड रेल परियोजना विकसित की जा रही है। अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल 17 सितंबर, 2024 को 12 डिब्बों की संरचना के साथ शुरू की गई है। ■

21वीं सदी का जम्मू-कश्मीर लिख रहा

विकास का नया अध्याय

'धरती पर स्वर्ग' के रूप में जम्मू-कश्मीर एक बार फिर से अपनी पहचान हासिल कर रहा है। यहां की जनता के साथ मिल कर केंद्र सरकार सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार रख रही है। खेल से लेकर खेत तक और शहर से लेकर गांव तक, नई औद्योगिक नीति से लेकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने दृढ़ता से काम किया है। पर्यटन, उद्योग, रोजगार, कारोबार के इसी विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का किया उद्घाटन...



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसमें 'धरती पर स्वर्ग' जम्मू-कश्मीर के हर क्षेत्र में विकास के लिए काम किया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक और सुदूर पहाड़ी इलाकों से लेकर दुर्गम स्थानों तक सड़क और रेल नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये के रोड और राजमार्ग के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 250 या इससे अधिक आबादी वाले 99 फीसदी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जा चुका है। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से सीधा कनेक्ट करना चाहती है ताकि व्यापार से लेकर पर्यटन को बढ़ावा मिले और दिलों की दूरियां भी खत्म हो।

बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों और सुहावने मौसम की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर हाल ही में साझा की गई तस्वीरों को देखने के बाद उनकी जम्मू-कश्मीर आने की उत्सुकता बढ़ गई थी। सोनमर्ग सुरंग के शुरू होने से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और कारगिल के लोगों का जीवन आसान होगा। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के बाद भी इस सुरंग के माध्यम से आसानी से गंतव्य तक पहुंचा जा सकेगा। सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग से संपर्क बना रहेगा और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सोनमर्ग सुरंग का निर्माण 2015 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ था।

जम्मू-कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल

जम्मू-कश्मीर के सुदूर पहाड़ी इलाकों तक सफर को आसान बनाने के लिए रोड और राजमार्ग का जाल बिछाया जा रहा है। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से चार महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।

जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर मार्ग

250 किलोमीटर की इस दूरी को 16,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसमें कुल 33 टनल होंगे जिसमें से 15 तैयार हो चुके हैं और 18 टनल पर काम जारी है। कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को तय करने में पांच घंटे कम लगेंगे। इस प्रोजेक्ट का कार्य दिसंबर-2025 तक पूरा हो जाएगा।

जम्मू-चेनानी-अनंतनाग

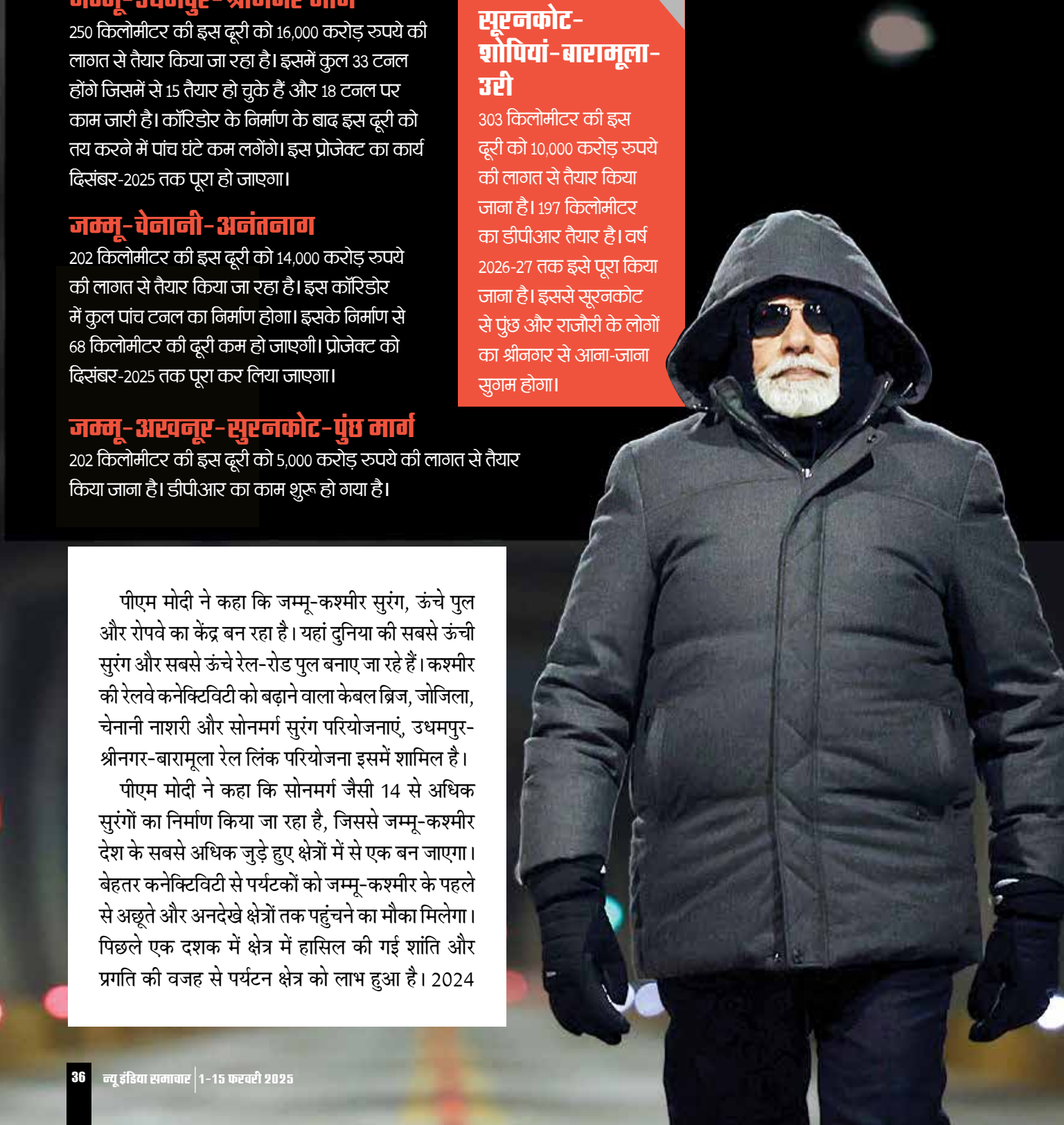
202 किलोमीटर की इस दूरी को 14,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में कुल पांच टनल का निर्माण होगा। इसके निर्माण से 68 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। प्रोजेक्ट को दिसंबर-2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जम्मू-अखनूर-सुरनकोट-पुंछ मार्ग

202 किलोमीटर की इस दूरी को 5,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाना है। डीपीआर का काम शुरू हो गया है।

सूरनकोट-शोपियां-बारामूला-उरी

303 किलोमीटर की इस दूरी को 10,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाना है। 197 किलोमीटर का डीपीआर तैयार है। वर्ष 2026-27 तक इसे पूरा किया जाना है। इससे सूरनकोट से पुंछ और राजौरी के लोगों का श्रीनगर से आना-जाना सुगम होगा।



पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सुरंग, ऊंचे पुल और रोपवे का केंद्र बन रहा है। यहां दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग और सबसे ऊंचे रेल-रोड पुल बनाए जा रहे हैं। कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला केबल ब्रिज, जोजिला, चेनानी नाशरी और सोनमर्ग सुरंग परियोजनाएं, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना इसमें शामिल है।

पीएम मोदी ने कहा कि सोनमर्ग जैसी 14 से अधिक सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जम्मू-कश्मीर देश के सबसे अधिक जुड़े हुए क्षेत्रों में से एक बन जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटकों को जम्मू-कश्मीर के पहले से अछूते और अनदेखे क्षेत्रों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। पिछले एक दशक में क्षेत्र में हासिल की गई शांति और प्रगति की वजह से पर्यटन क्षेत्र को लाभ हुआ है। 2024



में 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय व्यवसायों को लाभ हुआ है, जिसमें होटल, होमस्टे, ढाबे, कपड़ों की दुकान और टैक्सी सेवाएं भी शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर का यह नया युग है। 40 वर्ष के बाद क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लीग और खूबसूरत डल झील के आसपास कार रेसिंग का आयोजन किया गया। गुलमर्ग भारत की शीतकालीन खेलों की राजधानी बन रहा है, जहां चार खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी की जा चुकी है और इसके पांचवे संस्करण की भी मेजबानी कर रहा है। पिछले दो वर्ष में देश भर के 2,500 एथलीटों ने जम्मू-कश्मीर में विभिन्न खेल टूर्नामेंट में भाग लिया है। इस क्षेत्र में 90 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र से 4,500 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर को और भी सुंदर तथा समृद्ध बनाने के लिए काम किया जा रहा है जिसमें क्षेत्र के युवा, बुजुर्ग और बच्चों का निरंतर समर्थन मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर के लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगन से काम करके इस क्षेत्र और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहे हैं।

शीतकालीन पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्थानीय आजीविका को मिलेगा बढ़ावा

लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और एप्रोच रोड शामिल है। यह समुद्र तल से 8,650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। इससे शीतकालीन पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2028 मे जब जोजिला सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तब इस सोनमर्ग मार्ग के साथ जुड़कर श्रीनगर घाटी से लद्दाख के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-1 से न सिर्फ संपर्क सुनिश्चित होगा बल्कि दूरी भी 49 किमी से घटकर 43 किमी रह जाएगी। वाहनों की गति 30 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 70 किमी प्रतिघंटा हो जाएगी। बेहतर कनेक्टिविटी से रक्षा रसद को बढ़ावा मिलेगा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक विकास तथा सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ■

भगोड़े अपराधियों पर अब भारतपोल से कसेगी लगाम



भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने वाले अपराधियों की फेहरिस्त लंबी है। कई देशों से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल होने के चलते अपराधी इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में अब भारतपोल पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह भारतीय एजेंसियों और पुलिस को रियल टाइम सूचना साझा करने में तो सक्षम बनाएगी ही राज्यों की पुलिस भी सीधे इंटरपोल की ले सकेगी मदद...

साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी सहित अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव के कारण आपराधिक जांच में तेजी और रियल-टाइम में अंतरराष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सीबीआई ने भारतपोल पोर्टल विकसित किया है। सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यह उपलब्ध है और सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाएगा। दिल्ली में 7 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतपोल पोर्टल को बहुत विस्तृत एक्सरसाइज कर बनाया गया है। रियल-टाइम इंटरफेस इस पोर्टल की विशेषता है। यह अपराध नियंत्रण के लिए एजेंसियों के बीच सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से वैश्विक नेटवर्क के साथ

> **“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतपोल की शुरुआत के साथ अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन में भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। भारतपोल के माध्यम से भारत की हर एजेंसी और पुलिस फोर्स बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर जांच को गति दे सकेगी।**
>
> **- अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

भारतपोल के पांच प्रमुख स्तंभ

भारतपोल के पांच प्रमुख स्तंभ हैं जिसके माध्यम से सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता का एक तकनीकी मंच मिला है।



रियल-टाइम डेटा शेयरिंग, रेड कॉर्नर नोटिस और अन्य नोटिस को जारी करने के साथ-साथ दूसरे देश भी हमारे अनुरोध पर तेजी से काम कर सकेंगे।

भारतपोल पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करेगा, जिसमें रेड नोटिस और अन्य कलर-कोडेड इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। भारतपोल पोर्टल, फील्ड लेवल पुलिस अधिकारियों के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण बनेगा, इससे अपराध व सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय सहायता तक आसान और तेज पहुंच की सुविधा प्रदान कर भारतपोल अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को मजबूत करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई सालों तक भारत में अपराध कर दुनिया के अन्य देशों में भाग जाने वाले अपराधी कानूनों की पकड़ से बाहर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की पहुंच से बाहर रहे अपराधियों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए।

नई व्यवस्था से आतंकवाद जैसे अपराधों से निपटने में मिलेगी मदद

ड्रग्स, हथियारों और मानव तस्करी के साथ-साथ सीमा पार से होने वाले आतंकवाद जैसे अपराधों से निपटने में नई व्यवस्था से बहुत मदद मिलेगी। इस प्रकार के अपराधों के बारे में राज्यों की पुलिस भारतपोल के नेटवर्क से 195 देशों की पुलिस के साथ जानकारी साझा कर सकेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा अंतरराष्ट्रीय डेटा के उपयोग के संबंध में होगा। इसके तहत युवा अधिकारियों के लिए 19 प्रकार के इंटरपोल के डेटाबेस, एनालिसिस एवं अपराध रोकने की व्यवस्था खड़ी करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से साइबर अपराध की नई चुनौतियों से भी बेहतर ढंग और तेज गति से निपटा जा सकेगा।

कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कार विजेता 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। ■



गांव के विकास से राष्ट्र का विकास

भारत की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है तो देश की जीडीपी में भी कृषि क्षेत्र 18 फीसदी से ज्यादा का योगदान देता है... और इसीलिए यह विकसित भारत की नींव की सबसे मजबूत कड़ी है। इसी नींव को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव की शुरुआत की। मकसद है विकसित भारत- 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण...

गांव से जुड़े और वहां पले बढ़े लोग जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन भी एक छोटे से कस्बे के साधारण परिवेश में बीता और घर से निकले तो भी उनका अधिकांश समय गांव-देहात में ही गुजरा। इसकी वजह से वह गांव की न सिर्फ समस्याएं समझे बल्कि संभावनाओं को भी जान पाए। उनके मन में गांव-गरीब की सेवा का संकल्प जगा और समस्याओं के समाधान की प्रेरणा मिली। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बनें और उन्हें गांव में ही ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलें, पलायन न करना पड़े। गांव के लोगों का जीवन आसान हो इसीलिए, हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया।

जब इरादे नेक होते हैं तो नतीजे भी संतोष देने वाले होते हैं। केंद्र सरकार के बीते 10 वर्ष की मेहनत के परिणाम देश को मिलने लगे

सर्वे में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य

- देश में कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है जिसमें सामने आया कि साल 2011 की तुलना में ग्रामीण भारत में खपत यानी ग्रामीणों की क्रय शक्ति लगभग तीन गुना बढ़ गई है।
- इसका मतलब ग्रामीण लोग अपनी पसंद की चीजें खरीदने में पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं।

पहले गांव के लोगों को अपनी कमाई का **50%** से ज्यादा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च करना पड़ता था



- पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में भी खाने-पीने का खर्च 50 प्रतिशत से कम हुआ है।
- साथ ही, अन्य चीजें खरीदने में खर्चा बढ़ा है। इसका मतलब लोग अपना जीवन बेहतर बनाने पर खर्च कर रहे हैं।
- इसी सर्वे में एक और बड़ी बात सामने आई कि शहर और गांव में होने वाली खपत का अंतर कम हुआ है। पहले शहर का प्रति परिवार जितना खर्च खरीददारी पर करता था और अब धीरे-धीरे गांव वाला भी शहर वालों की बराबरी करने लगा है।

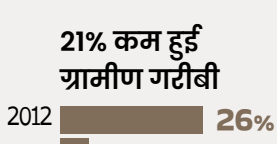
4 से 9 जनवरी तक चला ग्रामीण भारत महोत्सव 2025

ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन 4 से 9 जनवरी तक किया गया। इस महोत्सव का विषय 'विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण' रहा। इसका आदर्श वाक्य 'गांव बढ़े, तो देश बढ़े' रहा। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चा, कार्यशाला और मास्टरक्लास के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना रहा। इसके उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन पर ध्यान देने और टिकाऊ कृषि विधियों को अपनाकर उत्तर-पूर्व भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल रहा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अहम स्टडी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हाल ही में एक अहम स्टडी सामने आई है। बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि...

21% कम हुई ग्रामीण गरीबी





इंफ्रास्ट्रक्चर से मिली गांवों को गति-रोजगार

आज देश के ज्यादातर गांव हाइवे, एक्सप्रेसवे और रेलवे के नेटवर्क से जुड़े हैं।



4 लाख किमी सड़कें बनाई गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में।

94% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा है आज देश में।

- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं।
- गांव में बैंकिंग सेवाएं और **UPI** जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है।
- 2014 से पहले देश में एक लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे जो अब 5 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर पर सरकार की दर्जनों सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं।

हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बनें। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। सरकार का मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाएं और गांवों में रोजगार-स्वरोजगार के नए मौके भी बनें।



भविष्य की प्रौद्योगिकी का केंद्र बनेगा आंध्र प्रदेश

इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी का संगम सिर्फ समाज और जीवन में ही बदलाव नहीं लाता... अर्थव्यवस्था को भी गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन...

आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य की सरकार ने 'स्वर्ण आंध्र@2047' पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भरोसा दिलाया है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। रेल, रोड, फार्मा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी से लेकर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राज्य को केंद्र की ओर से प्राथमिकता दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश अपनी नवाचार की प्रकृति के कारण आईटी और प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा "अब समय आ गया है कि आंध्र प्रदेश भविष्य की प्रौद्योगिकियों का केंद्र बने।" 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। शुरुआती चरण में दो हरित हाइड्रोजन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक विशाखापत्तनम में होगा। विशाखापत्तनम दुनिया के उन कुछ शहरों में से एक होगा जहां बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाएं होंगी। यह हरित हाइड्रोजन केंद्र रोजगार के अनेक अवसर पैदा करेगा और आंध्र प्रदेश में एक विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करेगा।

वहीं प्रदेश के नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क परियोजना की आधारशिला रखी गई। आंध्र प्रदेश देश के उन तीन राज्यों में से एक है, जहां इस तरह का पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क विनिर्माण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा जिससे निवेशकों का उत्साह और विश्वास बढ़ेगा तथा स्थानीय फार्मा कंपनियों को लाभ मिलेगा।

आंध्र प्रदेश में शहरीकरण के अवसर को देखते हुए सरकार ने कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी। इसे क्रिस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्मार्ट सिटी चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक

हरित ऊर्जा

हरित ऊर्जा और टिकाऊ भविष्य के लिए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास पुद्दीमदका में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र है। इसमें लगभग 1,85,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह परियोजना 2030 तक भारत के 500 गीगावॉट के गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

रोजगार में होगी वृद्धि

अनकापल्ली जिले के नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। इससे हजारों रोजगार सृजित होंगे तो विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) और विशाखापत्तन-काकीनाडा पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र से निकटता के कारण आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत कृष्णपट्टनम औद्योगिक क्षेत्र (केआरआईएस सिटी) की भी आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केआरआईएस सिटी को एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जा रहा है। इससे लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।



आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और तकनीक का इतना बड़ा हब है। अब समय है कि प्रदेश भविष्य की प्रौद्योगिकियों का केंद्र बने।

– नरेंद्र मोदी, **प्रधानमंत्री**

मजबूत होता रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर

पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेलवे और सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की एवं आधारशिला रखी। इसमें विशाखापत्तन में दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से भीड़भाड़ कम होगी, संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्रीय सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

गलियारे का हिस्सा होगी जो हजारों करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगी और आंध्र प्रदेश में लाखों औद्योगिक नौकरियां पैदा करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य आंध्र प्रदेश को औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करना है। सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप भारत को विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के लिए दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जा रहा है।

विशाखापत्तनम के नए शहर में साउथ कोस्ट रेलवे जोन के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन मुख्यालय की स्थापना से क्षेत्र में कृषि और व्यापार गतिविधियों का विस्तार होगा, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के साथ आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे की क्रांति राज्य के परिदृश्य को बदल देगी।

आंध्र प्रदेश के तट सदियों से भारत के व्यापार के प्रवेश द्वार रहे हैं। केंद्र सरकार समुद्री अवसरों का उपयोग करने के लिए मिशन मोड में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। मत्स्य पालन में शामिल लोगों की आय और व्यवसाय बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं के प्रावधान और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ■



वैश्विक विकास में प्रवासी भारतीय सबसे आगे

प्रवासी भारतीयों ने हर तरह की कठिनाईयों को पार करते हुए न केवल अपने देश का नाम रौशन किया बल्कि ब्रांड एंबेसडर के तौर पर विदेशों में भारत के ध्वज को ऊंचा किया। ऐसे ही लोगों के कार्यों को सम्मान देने और एक-दूसरे से जुड़ने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक अहम मंच बना जिसका दायरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का किया उद्घाटन....

विश्व के अलग-अलग देशों में भारत के टैलेंट की सराहना हो रही है और दुनिया के बड़े देशों की इकोनॉमी के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक विकास में भी प्रवासी भारतीयों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत के टैलेंट को दुनिया सम्मान दे रही है। आज भारत के प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों में बड़े-बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ उस देश का विकास हो रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 3.5 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय विश्व के अलग-अलग देशों में काम कर रहे हैं और अपने देश के साथ उस देश की भी इकोनॉमी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और ओडिशा सरकार की साझेदारी में 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में किया गया। इस बार सम्मेलन का विषय 'विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान' रहा। तीन दिन तक चले इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय शामिल हुए। प्रवासी भारतीयों को देश के पर्यटन स्थल और धार्मिक महत्व से जुड़े स्थानों पर विशेष पर्यटक ट्रेन से घुमाने का कार्यक्रम शुरू किया गया

प्रवासियों के लिए पीएम मोदी की सलाह

- चुनौतियों को कैसे अवसरों में बदला, फिल्मों और वृत्त चित्रों के माध्यम से दिखाया जा सकता है।
- गिरमिटिया विरासत का अध्ययन और शोध करने के उद्देश्य से एक विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना का प्रस्ताव।
- विशेष प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से लगभग 150 लोगों को पर्यटन और आस्था से जुड़े 17 स्थलों का भ्रमण।
- छोटे शहर और गांवों का दौरा करके और अपने अनुभव साझा करके दुनिया को अपनी विरासत से जोड़ने का आग्रह।
- भारत दौरे पर गैर-भारतीय मूल के कम से कम पांच मित्रों को साथ लाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- युवा सदस्यों से भारत को बेहतर ढंग से समझने के लिए 'भारत को जानिए' प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की अपील।
- 'भारत में अध्ययन' कार्यक्रम और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) छात्रवृत्ति योजना का लाभ लें।
- भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास के सहयोग से उपलब्धि पाने वालों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत करें।
- स्थानीय या ऑनलाइन 'मेड इन इंडिया' खाद्य पैकेट, कपड़े और अन्य सामान खरीदें।



है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पीएम मोदी ने कहा प्रवासी भारतीय दिवस, भारत और उसके प्रवासियों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने वाली एक संस्था बन चुकी है। इसमें सब मिलकर भारत, भारतीयता, संस्कृति और प्रगति का उत्सव मनाते हैं। साथ ही अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। ओडिशा की महान भूमि, भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। सैकड़ों वर्ष पूर्व, ओडिशा के व्यापारियों और सौदागरों ने बाली, सुमात्रा और जावा

"मेरी एक appeal-Diaspora के सभी young Friends से भी है। आप भारत को जानिए Quiz में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। इससे भारत को जानने समझने में बहुत help मिलेगी। आप study in India programme का भी जरूर benefit लें।"

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जैसे स्थानों पर लंबी समुद्री यात्राएं की थीं। आज भी ओडिशा में बाली यात्रा उसी की याद में मनाई जाती है। सम्राट अशोक ने यहां शांति का मार्ग चुना था जबकि दुनिया तलवार की ताकत से साम्राज्यों का विस्तार कर रही थी। भारत की यह विरासत दुनिया को यह बताने के लिए प्रेरित करती है कि भविष्य बुद्ध में है, युद्ध में नहीं।

पीएम मोदी ने हमेशा प्रवासी भारतीयों को भारत का राजदूत माना है। भारतीय स्वाभाविक रूप से विविधता को अपनाते हैं और स्थानीय नियम एवं परंपराओं का सम्मान करते हुए जिस समाज में शामिल होते हैं, उसमें सहज रूप से एकीकृत होते हैं। भारतीय मेजबान देशों की सत्यनिष्ठा से सेवा करते हैं। उनके विकास और समृद्धि में योगदान देते हैं जबकि वे हमेशा भारत को अपने हृदय के करीब रखते हैं।

पिछले 10 वर्ष में भारत ने 25 करोड़ लोग को गरीबी से बाहर निकाला है और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में हर क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अक्षय ऊर्जा, विमानन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मेट्रो नेटवर्क और बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

विदेशों में भी निर्भीक भारतीय

केंद्र की सरकार प्रवासियों के सुख-सुविधाओं और उनकी सुरक्षा एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। संकट की स्थितियों में प्रवासियों की सहायता करना भारत की जिम्मेदारी है जो भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत को दर्शाता है। पिछले एक दशक में, दुनिया भर में भारतीय दूतावास और कार्यालय संवेदनशील और सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में चौदह नए दूतावास और वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं। मॉरीशस से 7वीं पीढ़ी के भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और सूरीनाम, मार्टिनिक और ग्वाडेलोप से 6वीं पीढ़ी के लोगों को शामिल करने के लिए ओसीआई कार्ड का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ■



वर्ष 2025 : भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण

जनभागीदारी से जनकल्याण

सभी को नए वर्ष के आगमन और नए कैलेंडर का इंतजार बहुत ही बेसब्री से रहता है। इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 जनवरी को नई दिल्ली में भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया। जनभागीदारी से जनकल्याण की थीम पर आधारित केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा डिजाइन और निर्मित इस कैलेंडर में न केवल किसान और महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों को दर्शाया गया है बल्कि यह समावेशिता, पारदर्शिता और भागीदारीपूर्ण शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी है प्रतिबिंब...

देश वर्ष 2014 से वर्ष 2025 में सुशासन के 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। भारत सरकार का कैलेंडर 2025 राष्ट्र की प्रगति और परिवर्तनकारी शासन के बारे में बताने के लिए लंबे समय से चली आ रही परंपरा में एक और अध्याय का प्रतीक है। सरकार ने परिवर्तनकारी शासन को रेखांकित करते हुए वर्ष 2025 के कैलेंडर के लिए जनभागीदारी से जनकल्याण यानी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण को मुख्य थीम के रूप में चुना है। कैलेंडर का अनावरण करते हुए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले एक दशक में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी शासन के स्पष्ट प्रभाव पर प्रकाश डाला। कैलेंडर में गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण और देश में बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने में परिवर्तनकारी शासन की भूमिका का उल्लेख किया गया है।

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास दर्शाता कैलेंडर



जनवरी

कैलेंडर की शुरुआत गरुड़ पुराण से लिए गए आदर्श वाक्य 'सर्वेषां मंगलं भूयात्' यानी सभी का कल्याण से होती है।



फरवरी

महिला सशक्तीकरण, कृषि, युवा और राष्ट्र की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इसका थीम 'अन्न का वर्धन हो' है।



मार्च

इस माह का थीम दुर्गासप्तशती का शक्ति रूपेण संस्थिता मंत्र है जो महिलाओं को शक्ति कहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान पर आधारित है।



अप्रैल

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत इसका थीम है। युवा को उठने, जागने और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करने का आह्वान किया गया है।



मई

पृष्ठ 'राष्ट्र समृद्धि में पनपता है' के मंत्र को दर्शाता है। यह पृष्ठ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित है।



जून

इसका थीम 'शुचिता से ही स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होता है' है। यह पेज स्वच्छता को समर्पित है।



जुलाई

इसका थीम 'व्यायाम हमेशा लाभदायक' है। यह पेज खेल के विश्व पटल पर तेजी से उभरते भारत की विकास यात्रा को दर्शाता है।



अगस्त

अगस्त का थीम जीवेत शरद शतम् पर आधारित है। यह वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाने की जानकारी देता है।



सितंबर

'उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि...' को इस महीने का थीम बनाया गया है। यहां पीएम मोदी के अर्थव्यवस्था में योगदान को दर्शाया गया है।



अक्टूबर

इस महीने का थीम ऐक्यं बलं सामंजस्य यानी एकता ही समाज का बल है।



नवंबर

इसका थीम अथर्ववेद से लिए गए माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या पर आधारित है। इस महीने आदिवासी गौरव दिवस है।



दिसंबर

इस माह का थीम अपरिमितं भव्यम् यानी भविष्य में असीम संभावनाएं हैं पर आधारित है।



13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित, कैलेंडर की समावेशिता हर भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के नागरिकों से जुड़ने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है। ग्राम पंचायतों से लेकर दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

कैलेंडर में चित्रों के माध्यम से देश की विकास यात्रा की कहानी बयां की गई है। यह भागीदारी पूर्ण शासन के महत्व को भी रेखांकित करता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का मूल उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों से आयुष्मान भारत जैसी पहल तक सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी की मुख्य भूमिका रही है। ■

नई ऊंचाई पर ले जाएगा कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाने का मंत्र

एक अध्यात्मिक नेता और दार्शनिक के रूप में 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस 12 जनवरी पर देश राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। युवाओं में आशा व वज्र संकल्पित हृदय के स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना ही आज विकसित भारत और युवा वर्ग के योगदान का आधार भी है। इस बार आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में पीएम मोदी ने युवाओं से कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाने का किया आह्वान...



राष्ट्रीय युवा दिवस को परंपरागत रूप से मनाने की विगत 25 वर्षों से जारी परंपरा तोड़ते हुए इस बार भारत सरकार के युवा कार्य विभाग की ओर से 10-12 जनवरी, 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम् में युवा संवाद का आयोजन किया गया। देशभर से चुन कर आए 3 हजार से ज्यादा ऊर्जावान युवा नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद सशरीर हमारे बीच होते, तो 21वीं सदी के युवा की इस जागृत शक्ति को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते।

देश की आर्थिक प्रगति के साथ युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत बहुत तेज गति से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। आज करीब-करीब भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत का सामर्थ्य इससे कई गुना बढ़ गया है।" भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पिछले दस साल यानी 2014 की तुलना में 6 गुना से अधिक यानी 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा, तब विकास का स्केल और बड़ा होगा। भारत को अगले दशक

सपनों का विकसित भारत यानी...

- जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा।
- जहां इकोनॉमी भी बुलंद होगी और इकोलॉजी भी समृद्ध होगी।
- जहां अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई के ज्यादा से ज्यादा अवसर होंगे।
- जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा स्किल्ड मैनपावर होगी।
- जहां युवाओं के पास सपने पूरा करने के लिए खुला आसमान होगा।

भारत हासिल कर रहा नई उपलब्धियां

- हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी, हर दिन एक नई **ITI**, हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब और हर दिन दो नए कॉलेज बन रहे हैं।
- देश में 23 **IITs** हैं, सिर्फ एक दशक में ट्रिपल आईटी की संख्या 9 से बढ़कर 25 और आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो चुकी है। 10 साल में एम्स तिगुने और मेडिकल कॉलेज दोगुने हो गए।
- 2014 में 9 के मुकाबले 46 शैक्षणिक संस्थानों को क्यूएस रैंकिंग।

अब राष्ट्रीय युवा नीति की बारी

देश के युवाओं की ऊर्जा और आकांक्षा को सही दिशा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र सरकार सतत विकास लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय युवा नीति 2024 का मसौदा तैयार कर रही है ताकि उनकी वास्तविक क्षमता को उभारा जा सके। इसका उद्देश्य युवा विकास के लिए क्षमताओं में सुधार करने में अनुभव से सीखने, युवा नेतृत्व एवं विकास, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल तथा सामाजिक समावेशन के लिए कार्य करना है।



आज तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद के दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वह अपनी निजी सफलता को टीम सफलता के रूप में विस्तार दे। यही स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

- 6.39 करोड़ लोगों को ग्रामीण साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) में मार्च, 2024 तक किया गया प्रशिक्षित। लक्ष्य 6 करोड़ का था।
- 10.2 फीसदी रह गई है 15-29 वर्ष के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 में। 2017-18 में 17.8 फीसदी थी।

3,00,00,000

युवाओं को मिला कुशल भारत मिशन की योजनाओं में प्रशिक्षण, इस मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग से संबंधित कौशलयुक्त करना है।

की समाप्ति तक 10 ट्रिलियन डॉलर के पड़ाव को पार करने की उम्मीद है। जब इतनी बड़ी इकोनॉमी होगी तो युवाओं का करियर आगे बढ़ेगा, अवसर भी अधिक होंगे। सबसे अधिक फायदा आज के नौजवानों को मिलेगा।

युवा महोत्सव के अंतिम दिन अपने संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि वर्तमान युवा पीढ़ी न सिर्फ देश के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन करेगी, बल्कि उस परिवर्तन की सबसे बड़ी लाभार्थी भी होगी। उन्होंने कहा कि हमें बस इस यात्रा में कंफर्ट जोन की आदत से बचना है। ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाना जरूरी है। यही जीवन मंत्र आपको सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तीकरण, खेल, संस्कृति, स्टार्टअप, बुनियादी ढांचे आदि जैसे विषयों पर प्रेरक प्रस्तुतियां देखीं। देश के युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अपने विचारों को लागू करने का सबसे शानदार माध्यम बन सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए देश के नौजवानों के साथ मित्रता का नाता है। मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है- विश्वास। इसी विश्वास ने मुझे MY-Bharat पोर्टल के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है- भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य, भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। ■



भारतीय मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस समारोह

भारत की वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक भारतीय मौसम विभाग

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की स्थापना 1875 में 15 जनवरी को हुई थी। आईएमडी ने 150 वर्ष में न केवल करोड़ों भारतीय की सेवा की है बल्कि यह देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गौरवशाली यात्रा भी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी की सटीकता पिछले दस वर्ष में बढ़ी है तो अब भारत को क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम और 2047 के मौसम विभाग के स्वरूप को दर्शाने वाला विजन डॉक्यूमेंट भी आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च...

मौसम विज्ञान, किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम विज्ञान की दक्षता को अधिकतम करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज उन आपदाओं की दिशा मोड़ने में कामयाबी मिल रही है जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। भारत मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े-बड़े चक्रवात और आपदाएं आईं लेकिन ज्यादातर में हम जनहानि को जीरो या मिनिमम करने में सफल हुए। इन सफलताओं में मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। विज्ञान और तैयारियों की इस एकजुटता से लाखों करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान में भी कमी आती है।

दुनिया के हर भूभाग में इंसानों ने मौसम और वातावरण को जानने

समझने की लगातार कोशिशें की हैं। इस दिशा में, भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित अध्ययन और अनुसंधान हुए हैं। यहां पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तरीके से परिभाषित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यहां वेद, संहिता और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर बहुत काम हुआ था। तमिलनाडु के संगम साहित्य और उत्तर में घाघ भड्डरी के लोक साहित्य में भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। मौसम विज्ञान केवल एक अलग ब्रांच नहीं था। इनमें खगोलीय गणना, जलवायु अध्ययन, पशु व्यवहार और सामाजिक अनुभव भी शामिल थे।

10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में हुआ अभूतपूर्व विस्तार

किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति विज्ञान के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में अन्वेषण और इनोवेशन नए भारत के स्वभाव का हिस्सा है। पिछले 10 वर्ष में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉप्लर मौसम रडार, स्वचालित मौसम स्टेशन, रनवे मौसम निगरानी प्रणाली, जिलावार वर्षा निगरानी स्टेशन, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैं। वर्ष 2024 में अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है।

90 फीसदी आबादी तक पहुंच रही मौसम की सटीक जानकारी

मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। सभी के लिए पूर्व चेतावनी सुविधा की पहुंच आज देश की 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी तक हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बीते 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे व्हाट्सएप पर भी पहुंच जाती है। मेघदूत मोबाइल एप जैसी सेवाएं लॉन्च की गई जहां देश की स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होती है। 10 साल पहले तक देश के केवल 10 प्रतिशत किसान और पशुपालक मौसम संबंधी सुझावों का इस्तेमाल कर पाते थे। आज यह संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। यहां तक की, बिजली गिरने जैसी चेतावनी भी लोगों को मोबाइल पर मिलने लगी है। पहले देश के लाखों समुद्री मछुआरे समंदर में जाते थे तो उनके परिजनों की चिंता बढ़ी रहती थी लेकिन अब, आईएमडी के सहयोग से उन्हें भी समय रहते चेतावनी मिल जाती है। रियल टाइम अपडेट्स से लोगों की सुरक्षा बढ़ी है। साथ ही कृषि और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों को ताकत भी मिल रही है। ■



> मौसम संबंधी प्रगति के कारण हमारी आपदा प्रबंधन क्षमता का निर्माण हुआ है। इसका लाभ पूरे विश्व को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूचनाएं दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मिशन मौसम की शुरुआत

भविष्य में भारत, मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए 'मिशन मौसम' लॉन्च किया गया। मिशन मौसम सस्टेनेबल भविष्य और भविष्य की तैयारी को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित कर उच्च-रिजॉल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों तथा उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटर को लागू कर देश को जलवायु के संदर्भ में स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। यह मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने एवं वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने मौसम संबंधी जागरूकता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन-2047 दस्तावेज भी जारी किया। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया।

दुनिया की मजबूत

समुद्री शक्ति बनता भारत

नौसेना, एक ऐसा शक्तिशाली बल है जो समुद्र की गहराई और लहरों के बीच न सिर्फ देश की सुरक्षा करता है बल्कि यह बल साहस, समर्पण और अनुशासन के जीवंत उदाहरण के साथ समुद्री सीमाओं की रक्षा का प्रतीक भी है। दुनिया की मजबूत समुद्री शक्ति बनने के क्रम में 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से तीन अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को किए समर्पित...

भारत की समुद्री ताकत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 15 जनवरी का दिन बहुत बड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की भूमि पर जहां नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, उसी धरती से 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने के लिए पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन का साथ-साथ कमिशन किया गया। देश के लोगों के लिए गर्व की बात है कि यह तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म भारत में बने हैं।

लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस और शिप इंडस्ट्री में देश का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसी से प्रेरणा लेते हुए भारत दुनिया की एक महत्वपूर्ण मेरीटाइम पावर (समुद्री क्षेत्रों पर किसी देश का राजनीतिक नियंत्रण और प्रभाव) बन रहा है। 15 जनवरी को पीएम मोदी ने जो तीन युद्धपोत देश को समर्पित किए वह इसकी एक झलक मात्र है। इन तीनों युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से भारत की सुरक्षा और प्रगति को नया सामर्थ्य मिला है।

पिछले कुछ वर्षों में देश ने समुद्री क्षेत्र में कई आधुनिक काम किए हैं जिसकी वजह से आज के भारत ने पूरे विश्व और खासकर

> **21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है, जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों Frontline Platforms मेड इन इंडिया हैं।**
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति है कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना से काम करता है। वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भूराजनैतिक गतिशीलता को दिशा देने में भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है। आर्थिक प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि अपने क्षेत्र के पानी





आत्मनिर्भरता की ओर भारतीय सेना

पिछले 10 साल में भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए काम हो रहा है। कर्नाटक में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री और सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेना ने 5 हजार से ज्यादा ऐसे साजो-सामान और उपकरणों की सूची तैयार की है जो अब विदेशों से नहीं मंगाई जाएगी। भारत का सैनिक, भारत में बने साजो-सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास ऊपर होता है। तेजस फाइटर प्लेन ने भारत की साख को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है।

40 नौसैनिक पोत में से भारतीय शिपयार्ड में बने 39

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर से प्रोडक्शन को और गति मिलेगी। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप और 7 सबमरीन को शामिल किया गया है। इन 40 नौसैनिक पोत में से 39, भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। इसमें भव्य-विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रु. से ज्यादा हो चुका है। भारत 100 से ज्यादा देश को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है।

की सुरक्षा की जाए और नेविगेशन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही व्यापार के लिए आपूर्ति के रास्ते और समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखा जाए। आतंकवाद, हथियार और ड्रग्स की तस्करी से इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखने की जिम्मेदारी भी नौसेना पर है। ऐसे में जरूरी है कि भारत समुद्र को सुरक्षित और समृद्ध रखने के लिए वैश्विक सहयोगी बने।

आईएनएस सूरत

पी15बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा व अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री के साथ अत्याधुनिक हथियार-सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क-केंद्रित क्षमताएं हैं।

राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात

- पी17ए स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरि, भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे बढ़ी हुई क्षमता के साथ समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा स्टील्थ युक्त उन्नत सुविधाओं के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है।
- पी75 स्कॉर्पीन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर, पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है।



'सेवा भाव' आध्यात्मिक संस्कृति का मुख्य आधार

भारत भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ एक टुकड़ा मात्र नहीं है, यह एक जीवंत भूमि है। एक जीवंत संस्कृति है, इस संस्कृति की चेतना अध्यात्म है। अगर हम भारत को समझना चाहते हैं तो हमें पहले अध्यात्म को आत्मसात करना होगा। यही वजह है कि अध्यात्म को आत्मसात करने के लिए दुनिया भर से लोग भारत पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन की परियोजना श्री राधा मदनमोहनजी मंदिर का किया उद्घाटन...

नौ एकड़ में फैले श्री राधा मदनमोहनजी मंदिर परिसर का डिजाइन और अवधारणा आध्यात्मिकता एवं ज्ञान की पूरी परंपरा को दर्शाता है। इसमें कई देवताओं वाला एक मंदिर, एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय और सभागार, उपचार केंद्र आदि शामिल है। इसके अलावा वृंदावन के 12 वनों से प्रेरित एक उद्यान भी यहां विकसित किया जा रहा है। मंदिर परिसर आस्था के साथ-साथ भारत की चेतना को समृद्ध करने वाला एक पवित्र केंद्र बनेगा। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षाओं के माध्यम से सार्वभौमिक भाईचारे, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने कहा दुनिया भर में इस्कॉन के अनुयायी भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति से एकजुट रहते हैं। श्रील प्रभुपाद स्वामी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वेद, वेदांत और गीता के महत्व को बढ़ावा दिया और भक्ति वेदांत को आम लोगों की चेतना से जोड़ा। 70 वर्ष की आयु में जब अधिकांश लोग अपने कर्तव्यों को पूरा हुआ मानते हैं तब श्रील प्रभुपाद स्वामी ने इस्कॉन मिशन की शुरुआत की और भगवान कृष्ण के संदेशों को हर कोने में फैलाते हुए पूरी दुनिया की यात्रा की। जब कोई अपनी आत्मा को इस सांस्कृतिक चेतना से जोड़ता है तो वह वास्तव में भारत को देख पाता है।

विशेषज्ञों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा शिप निर्माण में जितना निवेश किया जाता है उसका दोगुना सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है यानी अगर हम शिप निर्माण में 1 रुपये लगाते हैं तो अर्थव्यवस्था में करीब एक रुपये 82 पैसे का सर्कुलेशन होता है। अभी देश में 60 बड़े शिप निर्माणाधीन हैं। इनकी कीमत करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये है। यानी इतना पैसा लगने से करीब 3 लाख करोड़ रुपये का सर्कुलेशन देश की अर्थव्यवस्था में होगा। रोजगार के मामले में इसका 6 गुणा प्रभाव होता है। जहाजों के ज्यादातर सामान देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) से ही आते हैं। लिहाजा अगर 2,000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो उससे MSME सेक्टर में करीब 12 हजार रोजगार सृजित होते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि दुर्लभ खनिज संपदा, मछली जैसे समुद्री संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और इसके प्रबंधन की क्षमता को विकसित करना होगा। देश को व्यापार के लिए नए समुद्री रास्ते की तलाश और समुद्री संचार को मजबूत करने के लिए निवेश करने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार इस दिशा में कदम उठा रहा है। पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सबसे पहले मदद के लिए आने वाले देश के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। बीते कुछ महीनों में ही नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं, हजारों करोड़ रुपये के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि आसियान, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, अफ्रीकी देशों के साथ भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है। ■



आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मी और पेंशनर को सौगात

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया यह कदम कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 3,985 करोड़ रुपये की लागत से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनने वाले तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और वैज्ञानिकों को मिलेगा प्रोत्साहन...

निर्णय : केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। 1947 के बाद से सात वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा चुका है, जिनमें से आखिरी वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था।

प्रभाव : 45 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2016 से 2026 तक है। सातवें वेतन आयोग के 2026 में समाप्त होने से पहले आठवें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की गई है। पर्याप्त समय के दौरान आयोग राज्य सरकारों और सभी स्टेक होल्डर्स से इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेगी। चर्चा शुरू किए जाने से पूर्व आयोग के लिए चेयरमैन और दो सदस्यों का भी चयन किया जाएगा।



हम सभी को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और खपत को भी बढ़ावा मिलेगा।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

निर्णय : आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी।

प्रभाव : इसरो के नेक्सट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही यह श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के लिए भी स्टैंडबाय लॉन्च पैड के रूप में सहायता प्रदान करेगा। यह तीसरा लॉन्च पैड भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए लॉन्चिंग क्षमता को बढ़ाएगा। इसे 4 वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 3,984.86 करोड़ रुपये धनराशि की आवश्यकता है। इसमें लॉन्च पैड और संबंधित सुविधाएं भी शामिल है। ■

जन-गण-मन

कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति, अनूठी सांस्कृतिक विविधता

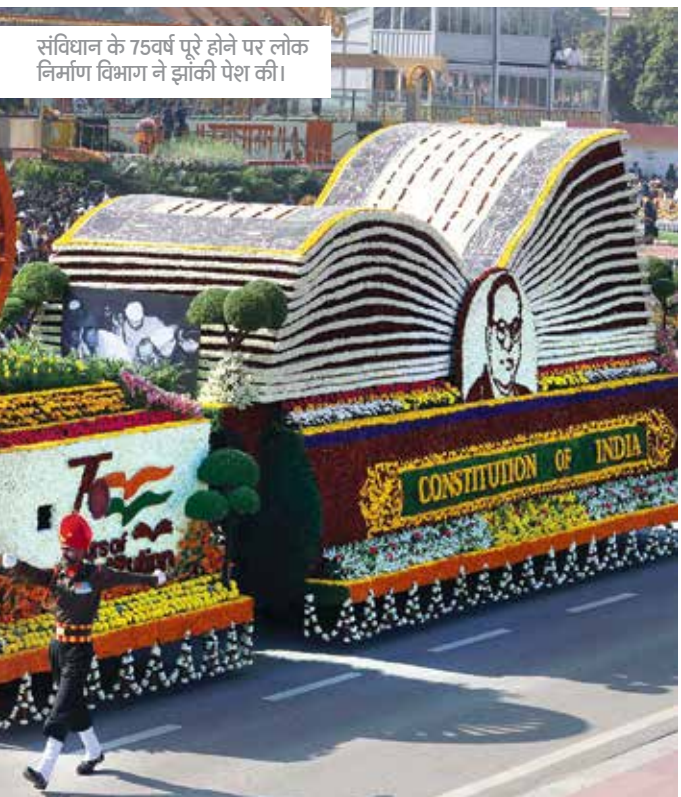
संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए और देश ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। कर्तव्य पथ पर जहां स्वदेशी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया तो वहीं 5,000 सांस्कृतिक कलाकारों ने 'जयति जया ममः भारतम' शीर्षक के तहत भारत की अनूठी सांस्कृतिक विविधता का पहली बार विजय चौक से सी हेक्सागोन तक प्रदर्शन किया गया। यह प्रस्तुति 11 मिनट तक चली जिसमें 45 से अधिक नृत्य शैलियां पेश की गई। 'स्वर्णिम भारत : विरासत और विकास' थीम पर 31 झांकियां पेश की गई। यह पहला मौका रहा जब तीनों सेना ने संयुक्त ऑपरेशन, समन्वय और एकीकरण को दर्शाती झांकी कर्तव्य पथ पर उतारी...







संविधान के 75वर्ष पूरे होने पर लोक निर्माण विभाग ने झांकी पेश की।





उत्तर प्रदेश : महाकुम्भ की झांकी।



सीआरपीएफ का महिला दस्ता।



'जयति जया मम: भारतम' शीर्षक के तहत 11 मिनट तक भारत की अनूठी सांस्कृतिक विविधता का पहली बार विजय चौक से सी हेक्सागोन तक 45 से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया गया।





पहली बार: जल, थल और वायु सेना का संयुक्त ऑपरेशन एक साथ दिखा। एकजुटता और एकीकरण की भावना को 'सशक्त और सुरक्षित भारत' के तहत स्वदेशी अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, आईएनएस विशाखापतनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता का भी प्रदर्शन।

बीएसएफ का ऊंट दस्ता।



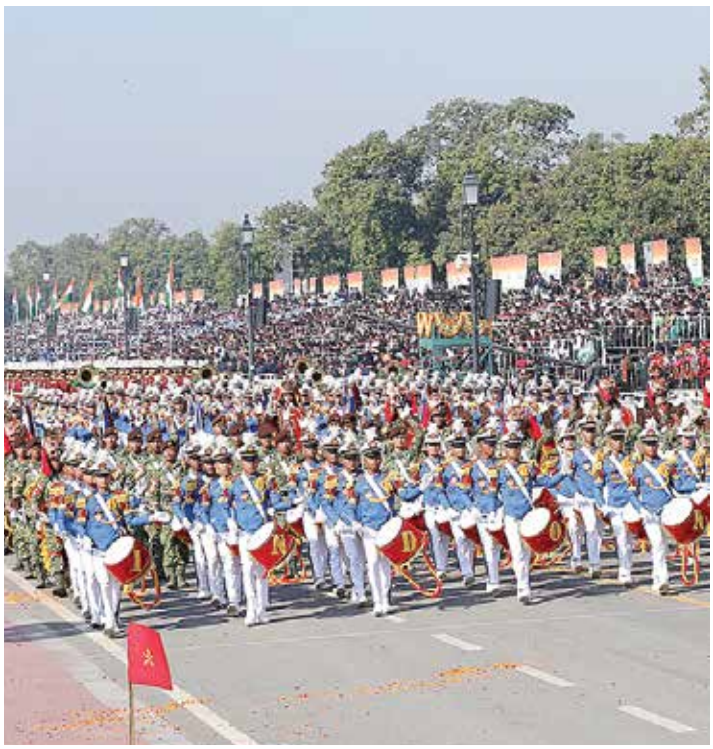






कै. डिंपल सिंह भाटी 12 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सलामी देने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी और साथ में विश्व रिकॉर्ड बनाया।





पहली बार इंडोनेशिया से 160 सदस्यीय मार्चिंग दल और 190 सदस्यीय बैंड दल ने कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ मार्च पास्ट किया।







मिसाइल 'प्रलय' पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल। डीआरडीओ ने विकसित किया है। मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है।150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है।



“कुंभ, पुष्करम, गंगा सागर मेला सामाजिक मेल-जोल, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देते हैं”



‘मन की बात’ कार्यक्रम हर बार राष्ट्र के सामूहिक प्रयास और लोगों की सामूहिक इच्छाशक्ति से जोड़ने का माध्यम बनती है। इसलिए वर्ष 2025 के प्रथम ‘मन की बात’ का अवसर विशेष था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस, संविधान की महत्ता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तकनीक, स्टार्टअप सहित सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने वाले महाकुम्भ जैसे मेलों पर विशेष बात की। प्रस्तुत है ‘मन की बात’ के अंश...

- **महान व्यक्तित्वों को नमन :** इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी-लंबी चर्चाएं हुईं। वो चर्चाएं, संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी, हमारी बहुत बड़ी धरोहर है।
- **राष्ट्रीय मतदाता दिवस :** 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। यह इसलिए अहम है, क्योंकि इस दिन ‘भारतीय निर्वाचन आयोग’ की स्थापना हुई थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को, बहुत बड़ा स्थान दिया है।
- **चुनाव आयोग को धन्यवाद :** मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा, जिसने समय-समय पर, हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जन-शक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीक की शक्ति का उपयोग किया।
- **एकता का महाकुम्भ :** चिरस्मरणीय जन-सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता-समरसता का असाधारण संगम। कुम्भ का उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। कुम्भ में गरीब-अमीर सब एक हो जाते हैं।
- **भारत की परंपरा :** ‘कुम्भ’, ‘पुष्करम’ और ‘गंगा सागर मेला’, हमारे ये पर्व, हमारे सामाजिक मेलजोल, सद्भाव और एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। ये पर्व भारत के लोगों को भारत की परंपराओं से जोड़ते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों ने संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पर बल दिया है वैसे ही हमारी परंपराएं और पर्व आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष को भी सशक्त करते हैं।
- **प्रतिष्ठा द्वादशी :** ‘पौष शुक्ल द्वादशी’ के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल ‘पौष शुक्ल द्वादशी’ 11 जनवरी को थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की यह द्वादशी, भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। इसलिए पौष शुक्ल द्वादशी का यह दिन एक तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन भी बन गया है।
- **स्पेस टेक्नोलॉजी में कीर्तिमान :** 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारत के वैज्ञानिक और इनोवेटर भविष्य की चुनौतियों का समाधान देने के लिए कितने दूरदर्शी हैं। हमारा देश, आज स्पेस टेक्नोलॉजी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं भारत के वैज्ञानिक, इनोवेटर और युवा उद्यमियों को पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं देता हूं।
- **स्टार्टअप के 9 साल :** हमारे देश में जितने स्टार्टअप 9 साल में बने हैं, उनमें से आधे से ज्यादा टिअर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। जब यह सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। जब यह सुनने को मिलता है कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टु, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्टअप के सेंटर बन रहे हैं तो मन आनंद से भर जाता है।
- **नेताजी को नमन :** नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूरदर्शी थे। साहस तो उनके स्वभाव में रचा-बसा था। इतना ही नहीं वह बहुत कुशल प्रशासक भी थे। महज 27 साल की उम्र में वह कोलकाता कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। उसके बाद मेयर की जिम्मेदारी भी संभाली। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। ■



Narendra Modi
@narendramodi

We are all proud of the efforts of all Government employees, who work to build a Viksit Bharat. The Cabinet's decision on the 8th Pay Commission will improve quality of life and give a boost to consumption.



रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा गया है। स्वाभाविक सी बात है, इस लक्ष्य को पाने में अभी कई सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। लेकिन हमें डटकर उन चुनौतियों का सामना करना है। चाहे वह Technology के front पर हों, या फिर Warfare के front पर, आने वाले समय में कई नए Challenges हमारे सामने आएँगे। RM



Amit Shah
@AmitShah

Congratulations to the central government employees on PM Shri @narendramodi Ji's decision to constitute the 8th Pay Commission in today's #CabinetDecisions. The move made to enhance the financial well-being of the employees demonstrates the Modi government's commitment to their welfare.



Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Historic reform on the horizon!

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri @narendramodi Ji, has approved the establishment of the Eighth Central Pay Commission for Central Government employees and pensioners.

This landmark commission, set to take effect from January 1, 2026, will recommend salary and pension revisions, ushering in a new era of financial empowerment.



Kiren Rijiju
@KirenRijiju

केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार का अभूतपूर्व निर्णय...

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति देकर सरकार ने बजट से पहले बड़ा उपहार दिया। यह निर्णय कर्मचारियों के जीवन और अधिक आसान बनाएगा और वो पूरी तत्परता से भारत निर्माण में अपना सहयोग देंगे।

#CabinetDecisions



Dharmendra Pradhan
@dpradhanbjp

The Cabinet decision on the 8th Pay Commission will boost welfare and benefit lakhs of central government employees.

Congratulate our hardworking employees of the central government. PM Shri @narendramodi ji remains committed to ensure the welfare and well-being of our citizens.

मोदी ने कहा- देश के सैन्य सामर्थ्य का मकसद विस्तारवाद नहीं, विकासवाद है

नौसेना को मिले सुरक्षा के तीन योद्धा



हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव का प्रमुख आधार सेवा भाव : मोदी

प्रधानमंत्री ने मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन



प्रधानमंत्री ने बरसों-उन्नत पूर्वानुमानों ने व्यापक के कवरेज होने वाले आर्थिक नुकसान को बहुत कम किया

भूकंप की चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए : मोदी



मिशन मौसम से अगले पांच साल में दिखेंगे कई बदलाव



प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में Z-मोड़ सुरंग की शुरुआत की

सोनमर्ग सुरंग से कनेक्टिविटी के साथ अब टूरिज़म को लगेंगे नए पंख: मोदी



भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश



भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 1000 किमी तक पहुंच गई है। इस बड़े नेटवर्क के साथ, भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा की शुरुआत की थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को नई मेट्रो परियोजनाओं और नमो भारत का उपहार दे रहे हैं।

'परीक्षा पे चर्चा': पीएम मोदी और छात्रों के बीच संवाद

कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 3.25 करोड़ पंजीकरण बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी शामिल हो रहे हैं



1 फरवरी 2025

भारतीय तटरक्षक दिवस

वयं रक्षामः



“

भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर, मैं उनके सभी कर्मियों और कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। समुद्री सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण की देखभाल के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय है। देश उनकी अटूट सतर्कता और सेवा के लिए उन्हें सलाम करता है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री





न्यू इंडिया समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 फरवरी, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 26-30 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 27 जनवरी 2025, कुल पृष्ठ-64)

प्रधान संपादक:
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
योगेश कुमार बवेजा,
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि.,
बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1,
नई दिल्ली-110020